कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

lnL;rk : +91(11) 23005798

Qksu (dk-) : +91(11) 23381428

QSDl : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

संगठनात्मक गतिविधियां

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का केरल प्रवास.. 6

सरकार की उपलब्धियां

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ... 8

प्रधानमंत्री ने इको-फ्रेंडली ई-बोट लांच तथा ई-रिक्शा वितरित किए...... 9

भारत 7.65 फीसदी की उच्च विकास दर रखने में कामयाब..................... 10

वैचारिकी

एकात्म मानववाद : एक अध्ययन

पी. परमेश्वरन.. 11

श्रद्धांजलि

बलराज मधोक नहीं रहे... 13

लेख

अगस्ता रिश्वत के तार कहां तक?

– बलबीर पुंज.. 14

अन्य

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव-प्रचार.. 16

केरल विधानसभा चुनाव-प्रचार.. 18

पं. बंगाल विधानसभा चुनाव-प्रचार... 20

गाजियाबाद (उप्र) में 'ग्राम उदय से भारत उदय' कार्यक्रम....................... 22

संसद में बहस : अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामला............................ 24

महामंत्री प्रतिवेदन... 28

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को **बुद्ध पूर्णिमा** की हार्दिक शुभकामनाएं!

फेसबुक

सोशल मीडिया से...

twitter

श्री नरेन्द्र मोदी

हिंसा और भ्रष्टाचार की राजनीति को अस्वीकार करने और विकास को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा को चुनने की तत्काल आवश्यकता है। यूडीएफ और एलडीएफ को समायोजन, समझौते और भ्रष्टाचार की राजनीति की कला में महारत हासिल है। कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया है। जो पश्चिम बंगाल और केरल में विरोधाभासी आवाज में बोलते हैं, उन्हें कैसे केरल की विकास यात्रा को सौंपा जा सकता है?

श्री अमित शाह

डीएमके और एआईएडीएमके के राज में तमिलनाडु उद्यमशीलता, मेहनत और उद्योगों की जगह भ्रष्टाचार का प्रतीक बनकर रह गया है। डीएमके और एआईएडीएमके में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही भ्रष्ट हैं और दोनों ने तमिलनाडु की जनता को विकास से दूर रखने का काम किया है। कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के यूपीए शासन में 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले किये- 2जी, कॉमनवेल्थ, हेलीकॉप्टर, कोल जैसे कई घोटाले यूपीए सरकार की तो झलकियां भर है। पिछले 50 वर्षों से तमिलनाडु ने दो पार्टियों और दो परिवारों का शासन देखा है, इससे मुक्ति पाने का एक अवसर 2016 के विधान सभा चुनाव है।

श्री नितिन गडकरी

सड़क मंत्रालय सूखे से लड़ने में जल संरक्षण के लिए अपना योगदान देगा।

श्री राधामोहन सिंह

एनआरआरआई की डबल हॉप्लाएड से विकसित धान प्रजातियों की पैदावार अधिक होगी। इससे किसानों को चावल के बीज नहीं खरीदने पड़ेंगे।

श्री रविशंकर प्रसाद

ई-वाणिज्य क्रांति के माध्यम से 'ट्रांस्फॉर्मिंगइंडिया।' भारतीय डाक 'कैश ऑन डिलिवरी' संग्रह 1300 करोड़ पहुंचा।

पाथेय

कार्यकर्ताओं को जोड़ना, उनको प्रशिक्षित करना, उनको समपर्ण भाव से काम करने की प्रेरणा देना। उनके लिए निरन्तर प्रवास करने वाले, योजना बनाने वाले कार्यकताओं की भी आवश्यकता है। यह सारा काम करने के लिए साधन भी जुटाने होंगे और यह संगठन के सारे पहलुओं के ऊपर विस्तार से विचार करने की जरूरत है। हम इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे, किन्तु एक ही उद्देश्य एक ही लक्ष्य को लेकर बढ़ने वाले और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में और इकाइयों में सामंजस्य आवश्यक है।

- कुशाभाऊ ठाकरे

सम्पादकीय

कांग्रेस के लिए परिवार हित सिद्धांत और नैतिकता से ज्यादा महत्वपूर्ण है

संसद में अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले पर हाल ही में हुई बहस से यह साफ हो गया है कि अपने शासनकाल के भ्रष्टाचार से कांग्रेस घबराई हुई है। अब जबकि इसमें कोई संदेह नहीं कि अगुस्ता वेस्टलैंड खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस इसे अपने नेतृत्व पर हमला मान रही है। यहां तक कि इसने लोकतंत्र बचाने के नाम पर मार्च तक आयोजित कर डाला। इस मार्च में राबर्ट वढ़ेरा के पोस्टर से यह साबित हो गया कि कांग्रेस क्या चाहती है। यह ध्यान देने योग्य है कि जबकि एक ओर राबर्ट वढ़ेरा पर तेज गति से जांच चल रही है, वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी दोनों नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं। कांग्रेस केन्द्र सरकार पर दबाव बनाकर जांच में अड़ंगे पैदा करना चाहती है, ताकि अपने शीर्ष नेतृत्व के दामन को बचा सके। लेकिन सरकार को उस जनादेश का सम्मान करना है जो कांग्रेस के घोटालों एवं भ्रष्टाचार के विरूद्ध दिया गया है।

यह अब भी लोगों के दिमाग में ताजा है कि किस प्रकार यूपीए शासनकाल में कांग्रेस एवं भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन गये थे। स्थिति इस हद तक खराब हो गई थी कि शायद ही कोई दिन ऐसा होता था, जब किसी घोटाले का खुलासा नहीं हुआ हो। अलग-अलग तरह के अनगिनत घोटालों में 2जी, आदर्श सोसाइटी, कोयला, सीडब्ल्यूजी, अगुस्ता वेस्टलैंड आदि प्रमुख घोटाले थे। इसके अलावा जिस प्रकार की नीतिगत पंगुता की शिकार यूपीए सरकार थी, विभिन्न घोटालों पर जांच पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद काले धन पर एसआईटी का गठन नहीं किया गया- इससे कांग्रेस के मंसूबे साफ हाते हैं।

कांग्रेस ने ना केवल जनता के नजरों में अपनी बची-खुची प्रतिष्ठा गिरा दी, बल्कि सभी राजनैतिक संस्थाओं का दुरूपयोग कर उन्हें खोखला कर दिया। अब जबकि जांच एजेंसियां नियमानुसार कार्रवाई कर रही है कांग्रेस को अपने कुकर्मों के उजागर होने का भय सता रहा है। यह वाकई शर्मनाक है कि जब इटली की अदालत ने रिश्वत देने वालों को दण्डित कर दिया, यूपीए सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई।

हर तरफ से इस बात की ओर इशारा जाता है कि किसी न किसी बहाने अगुस्ता पर कार्रवाई रोकी गई, जैसाकि रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान में किसी 'अदृश्य हाथ' को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। यह अब भी रहस्य है कि इटली में घूस देने वालों पर तो कार्रवाई हुई, पर जिन्हें घूस दिया गया उन पर कांग्रेस कार्रवाई करने से हिचकती रही। अब समय आ गया है कि यह साबित किया जाय कि भारत में कोई भी कितना ही बड़ा क्यों न हो, कानून से खेल नहीं सकता।

कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी बन गई है जो अवसरवादी राजनीति और भ्रष्टाचार की पर्याय है। उत्तराखंड में इसके मुख्यमंत्री विधायकों के खरीद-फरोख्त में स्टिंग में पकड़े जाते हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार की जांच चल रही है और केरल के मुख्यमंत्री उमेन चाण्डी का नाम घोटाले में आ चुका है। यह केरल में कम्युनिस्टों के विरुद्ध चुनाव लड़ रही है और पश्चिम बंगाल में इन्हीं कम्युनिस्टों से इसका गठबंधन है। कांग्रेस किसी राष्ट्र हित के मुद्दे पर सड़क पर नहीं उतरती, लेकिन यदि 'परिवार' पर कोई आंच आती है तब लोकतंत्र के नाम पर ये हाय-तौबा मचाती है। इससे साफ है कि कांगेस अब पूरी तरह से वंशवादी राजनीति के शिंकजे में है और सिद्धांतों एवं नैतिकता से ऊपर इसके लिए 'परिवार हित' है। कांग्रेस के इन्हीं तौर-तरीकों से अब यह अतीत की पार्टी बन गई है जिससे भविष्य की कोई उम्मीद नहीं बांधी जा सकती।

संगठनात्मक गतिविधियां : भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का केरल प्रवास

'केरल में आकाश, पाताल और जल – कोई ऐसी जगह नहीं बची, जहां कोई भ्रष्टाचार न हुआ हो'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 5 मई को केरल के पथनमथिता, कोट्टायम और परावूर की रैली को संबोधित किया। उन्होंने केरल की जनता से राज्य की भ्रष्टाचारी कांग्रेस-नीत यूडीएफ सरकार को जड़ से उखाड़ कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत और विकसित केरल के नवनिर्माण का आह्वान किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2016 के विधान सभा चुनाव केरल और केरल की जनता के भविष्य के लिए अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों से केरल में बारी-बारी से कांग्रेस की अगुआई वाली यूडीएफ गठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी की एलडीएफ गठबंधन की सरकार रही है, लेकिन दोनों सरकारों ने न तो केरल के विकास के लिए कुछ किया और न ही केरल की जनता के जीवन में बदलाव लाने के लिए कुछ किया। उन्होंने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ, दोनों ने केरल के विकास को अवरुद्ध करके रख दिया है। श्री शाह ने कहा कि केरल की जनता एलडीएफ या यूडीएफ में से किसी एक को चुनने के लिए वोट नहीं करती, बल्कि वह तो एक को सत्ता से बेदखल करने के लिए वोट करती है, दूसरा तो अपने आप सत्ता में आ जाता है। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों का एक मात्र लक्ष्य किसी तरह से सत्ता प्राप्ति करना है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है और न ही इन दोनों में कोई अंतर है। उन्होंने कहा कि ये वोट बैंक की राजनीति नहीं तो और क्या है, यह देश की जनता को धोखा देना नहीं तो और क्या है कि एलडीएफ और यूडीएफ पश्चिम बंगाल में तो मिलकर लड़ रही है, जबकि केरल में जनता को बस दिखाने के लिए एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रही है।

केरल की कांग्रेस-नीत यूडीएफ सरकार पर करारा प्रहार करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने केरल में भ्रष्टाचार और सरकार दोनों को एक-दूसरे का पर्याय बना दिया है। उन्होंने कहा कि केरल में भ्रष्टाचार सब जगह व्याप्त है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ढूंढना है तो केरल में ढूंढिए, आकाश, पाताल और जल – कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां कोई भ्रष्टाचार न हुआ हो। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केरल सरकार का आधा बजट तो घोटाले की भेंट चढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र में भी यूपीए सरकार के दौरान घोटालों की झड़ी लगा दी थी। उन्होंने कहा कि जमीन पर आदर्श सोसायटी घोटाला, जल में सबमरीन घोटाला, हवा में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर एवं टूजी घोटाला और पाताल में कोयला घोटाला, खेल में कॉमनवेल्थ घोटाला, यानी कि कोई ऐसी जगह नहीं बची, जहां कांग्रेस ने कोई भ्रष्टाचार न किया हो। अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वत कांड में यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन

रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया कि आखिर किसके इशारे पर हेलीकॉप्टर की फील्ड ट्रायल देश की बजाय विदेश में कराये गए, आखिर क्यों टेंडर को ओरिजिनल मैनुफैक्चरिंग कंपनी की जगह दलाली करने वाली कंपनी को दे दी गई, देश की जनता इसका सच जानना चाहती है।

भाजपा अध्यक्ष ने केरल में खराब कानून एवं व्यवस्था पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की अगुआई वाली यूडीएफ सरकार में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। उन्होंने कहा कि केरल में दिन-दहाड़े दलित बच्ची का बलात्कार होता है, फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन केरल की सरकार सोयी रहती है, उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, मुख्यमंत्री भी चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि केरल में दलित महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का जिम्मेवार आखिर कौन है?

श्री शाह ने कहा कि हमारा कोई हिडेन एजेंडा नहीं है, हमारा बस एक ही एजेंडा है और वह है एलडीएफ और यूडीएफ की भ्रष्टाचारी सरकारों को केरल से जड़ से उखाड़ फेंकना। उन्होंने कहा कि जनता में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि यदि भाजपा केरल में सत्ता में आती है तो राज्य में हिंसा होगी और कम्युनल हार्मनी खराब होगी। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी हास्यास्पद बात हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी "सबका साथ, सबका विकासश के सिद्धांत पर काम करती है, 14 राज्यों में हमारी सरकारें हैं और कहीं भी, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई, इसके ठीक उलट हमें तो समाज के सभी वर्गों का स्नेह और आशीर्वाद मिला है।" भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम पर हिंसा का आरोप लगाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा हमारे कई कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और केरल की चाहे एलडीएफ की सरकार हो या फिर कांग्रेस की यूडीएफ सरकार, दोनों मूकदर्शक बनी रही। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उनके बलिदान की नींव पर एक विकसित केरल का निर्माण होगा और यहां पर भाजपा-नीत राजग सरकार बनेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम पर हिंसा का आरोप लगाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा हमारे कई कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और केरल की चाहे एलडीएफ की सरकार हो या फिर कांग्रेस की यूडीएफ सरकार, दोनों मूकदर्शक बनी रही। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उनके बलिदान की नींव पर एक विकसित केरल का निर्माण होगा और यहां पर भाजपा-नीत राजग सरकार बनेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने वोट बैंक की राजनीति के चलते केरल के लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव और अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस और कम्युनिस्ट की तरह पक्षपात की राजनीति में यकीन नहीं रखती है। उन्होंने कहा, ''मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि केरल में भाजपा की सरकार आती है तो किसी के साथ भी भेदभाव या अन्याय नहीं होगा, भाजपा राज्य के सर्वांगीण और समान विकास के प्रति प्रतिबद्ध है।'' भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केरल में कम्युनिस्ट 96 वर्षीय अच्युतानंद जी को आगे कर चुनाव लड़ रही है लेकिन वह चुनाव जीतने पर कभी भी अच्युतानंद को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी वरन कम्युनिस्ट का चेहरा विजयन होंगे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि श्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा-नीत केंद्र सरकार ने पिछले 20 महीनों से गरीबों, शोषितों और वंचितों के उत्थान तथा सामाजिक कल्याण के लिए अनवरत कार्य किया है और अनेकों परिवर्तनात्मक योजनाओं की नींव रखी है जिसके आशातीत परिणाम धरातल पर दिखने शुरू हो गए हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री जन-धन योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना हो, जीवन सुरक्षा बीमा हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्ट-अप इंडिया हो या फिर स्टैंड-अप इंडिया हो। श्री शाह ने कहा कि विकास के जरिये गरीबों की सेवा और उनके जीवन-स्तर में सुधार लाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि एक विकसित और मजबूत केरल के लिए राज्य में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हो जाएं ताकि राज्य में किसी के साथ भेदभाव और अन्याय न हो सके। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि हिंसा और भ्रष्टाचार मुक्त केरल के नवनिर्माण के लिए भाजपा को बहुमत देकर राज्य में सेवा का एक मौका दें। ■

सरकार की उपलब्धियां

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ

तीन वर्षो में 5 करोड़ लाभार्थियों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 मई को बलिया में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य अगले तीन वर्षो में गरीबी रेखा से नीचे के पांच करोड़ लाभार्थियों को रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करना है। 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाए जाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सदी में, दुनिया के सभी श्रमिकों का उद्देश्य विश्व को एकजुट करने की दिशा में होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का प्राथमिक उद्देश्य गरीबों के कल्याण पर केन्द्रित रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछले दो वर्षो में केन्द्र सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाए गये विभिन्न कदमों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि बलिया क्रांतिकारी मंगल पांडे की भूमि है। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास दशकों से प्रभावित रहा है, अब इस क्षेत्र में संपर्क को मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जबरदस्त संसाधनों का आबंटन कर रही है। उन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण की त्वरित प्रगति का भी उल्लेख किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश जिसने अनेक-अनेक प्रधानमंत्री दिये, लेकिन क्या कारण कि हमारी गरीबी बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। गरीबों की संख्या भी बढ़ती गई। हमारी नीतियों में ऐसी क्या कमी थी कि हम गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिये तैयार नहीं कर पाए। ऐसा क्या कारण था कि हमने गरीबों को सिर्फ गरीबी के बीच जीना नहीं, लेकिन हमेशा सरकारों के पास हाथ फैलाने के लिए मजबूर करके छोड़ दिया, उसके जमीर को हमने खत्म कर दिया। गरीबी के खिलाफ लड़ने का उसका हौंसला हमने तबाह कर दिया।

श्री मोदी ने कहा कि करीब एक करोड़ दस लाख से भी ज्यादा ऐसे परिवार हैं, जिनको मैंने कहा था कि अगर आप खर्च कर सकते हो तो रसोई गैस की सब्सिडी क्यों लेते हो? क्या आप पांच-दस हजार रुपया का बोझ नहीं उठा सकते साल का। क्या आप सब्सिडी स्वतः छोड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा कि सिर्फ बातों-बातों में कहने पर प्रधानमंत्री की बात को गले लगाकर एक करोड़ दस लाख से ज्यादा परिवारों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। श्री मोदी ने कहा कि गरीबों के लिए जो सब्सिडी छोड़ेगा वो पैसा सरकार की तिजोरी में नहीं जाएगा। वो पैसे गरीबों के घर में जाएंगे। एक साल में ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।

उन्होंने कहा कि 1955 से रसोई गैस देने का काम चल रहा है। इतने सालों में 13 करोड़ परिवारों को रसोई गैस मिला। सिर्फ 13 करोड़ परिवारों को करीब साठ साल में, हमने एक साल में तीन करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई का गैस दे दिया। जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी वो गैस सिलंडर गरीब के घर में पहुंच गया।

श्री मोदी ने कहा कि अभी मैं पिछले हफ्ते झारखंड में एक योजना लागू करने के लिए गया था, झारखंड में कोई चुनाव नहीं है। मैं कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश में एक योजना लागू करने गया था, वहां पर कोई चुनाव नहीं है।

मैंने 'बेटी बचाओ' अभियान हरियाणा से चालू किया था, वहां कोई चुनाव नहीं है। ये बलिया में ये रसोई गैस का कार्यक्रम इसलिए तय किया कि उत्तर प्रदेश में जो एवरेज हर जिले में जो रसोई गैस है, बलिया में कम से

कम है, इसलिये मैं बलिया आया हूं। ये ऐसा इलाका है, जहां अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 100 में से मुश्किल से आठ परिवारों के घर में रसोई गैस जाती है। इसलिये मैंने आज बलिया में आकर के देश के सामने इतनी बड़ी योजना लागू करने का निर्णय किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने हरियाणा में 'बेटी बचाओ' इसलिये कार्यक्रम लिया था, क्योंकि हरियाणा में बालकों की संख्या की तुलना में बेटियों की संख्या बहुत कम थी। बड़ी चिंताजनक स्थिति थी और इसलिए मैंने वहां जाकर के खड़ा हो गया और उस काम के लिए प्रेरित किया और आज हरियाणा ने बेटी बचाने के काम में हिन्दुस्तान में नम्बर एक लाकर के खड़ा कर दिया।

श्री मोदी ने कहा कि मैं इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया में इसलिये आया हूं, क्योंकि हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अगर पूर्वी हिन्दुस्तान पश्चिमी हिन्दुस्तान की बराबरी भी कर ले तो इस देश में गरीबी का नामोनिशान नहीं रहेगा, मेरा मानना है। मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मेरा बिहार, मेरा पश्चिम बंगाल, मेरा असम, मेरा नॉर्थ ईस्ट, मेरा ओड़िशा, ये ऐसे प्रदेश हैं कि अगर वहां विकास गरीबों के लिए पहुंच जाए, तो गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हम सफल हो जाएंगे।

इससे पहले, प्रधानमंत्री ने वाराणसी के डीएलडब्ल्यू मैदान पर लाभार्थियों को ई-रिक्शा वितरित किए और उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र ज्ञान प्रवाह का भी दौरा किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वाराणसी के प्रमुख लोगों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे वाराणसी में साफ-सफाई सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने और वाराणसी को सबसे साफ शहरों में से एक बनाने का आह्वान किया। ■

प्रधानमंत्री ने इको-फ्रेंडली ई-बोट लांच तथा ई-रिक्शा वितरित किए

मुख्य बिंदु

- अस्सी घाट पर इको-फ्रेंडली ई-बोट लांच की
- लाभार्थियों को ई-रिक्शा वितरित किए
- सांस्कृतिक अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र ज्ञान प्रवाह का दौरा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 मई को अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के अस्सी घाट पर पर्यावरण अनुकूल ई-बोट्स लांच की। अस्सी घाट पर उपस्थित लोगों को संबोधित करने के लिए मंच पर आने से पहले प्रधानमंत्री ने नाव चलाने वालों से बातचीत की और गंगा नदी में ई-बोट पर कुछ देर सवारी की।

इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ई-बोट्स प्रदूषण घटाएंगी, पर्यटकों को अच्छा अनुभव देंगी और कम कीमत वाले ईंधन से लाभार्थियों को पर्याप्त राशि की बचत होगी। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे इस बचत राशि का उपयोग अपनी युवा पीढ़ी के लाभ के लिए करें।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का ध्यान ऐसी योजनाएं बनाने पर है, जिनसे लोग मजबूत होंगे। ये गरीबों को सशक्त बनाएंगी ताकि वे गरीबी से लड़ सकें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के स्वदेशी नेवीगेशन उपग्रह नेटवर्क को 'नाविक' नाम दिया गया है, यह उन लाखों लोगों के सम्मान में है, जो अपनी आजीविका नावों से कमाते हैं। ■

भारत 7.65 फीसदी की उच्च विकास दर रखने में कामयाब : वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि वैसे तो एशिया-प्रशांत क्षेत्र अब भी विश्व का विकास इंजन बना हुआ है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र की विकास दर पिछले साल के अनुमानित 5.9 फीसदी से घटकर वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में 5.7 फीसदी रह जाएगी। श्री जेटली ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत वर्ष 2015-16 में 7.65 फीसदी की ऊंची आर्थिक विकास दर हासिल करने में कामयाब रहा, जबकि पिछले साल यह 7.2 फीसदी आंकी गई थी। इस क्षेत्र के निर्धनतम देशों में विकास एवं गरीबी उन्मूलन में भागीदार बनने की भारतीय प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के एडीएफ-12 के तहत अपना अंशदान बढ़ाकर 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है।

वित्त मंत्री 4 मई को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में आयोजित एशियाई विकास बैंक की 49वीं वार्षिक आम बैठक के कारोबारी सत्र को संबोधित कर रहे थे।

एडीबी की भूमिका का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र जिस तरह से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है, ठीक उसी तरह से समय पर मूल्यवान योगदान करने संबंधी एडीबी की क्षमता पर गौर किया जा रहा है। वित्त मंत्री श्री जेटली ने विशेष जोर देते हुए कहा कि एडीबी को अभिनव परियोजनाओं के लिए अपनी ओर से सहायता देते हुए परिवर्तन का वाहक बनने की जरूरत है, जो संभवत: स्थानीय प्रयासों के जरिये संभव नहीं है।

उन्होंने कहा कि एडीबी के रेजीडेंट मिशनों का सशक्तिकरण और निर्णय लेने में प्रत्यायोजन एवं विकेन्द्रीकरण कुछ सुधार संबंधी अनिवार्यता हैं।

वित्त मंत्री ने सुधारों पर निरंतर जोर देने की बात को रेखांकित किया ताकि एडीबी को एक बेहतर और बड़े एमडीबी में तब्दील किया जा सके। ■

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत गत सप्ताह 104 गांवों में पहुंची बिजली

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत गत सप्ताह (25 अप्रैल से 01 मई, 2016) देश भर के 104 गावों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। इन गावों में से 17 गांव अरुणाचल प्रदेश, 17 असम, 16 झारखंड, 10 राजस्थान, 4 बिहार, 4 छत्तीसगढ़, 16 ओडिशा, 7 मध्य प्रदेश, 4 मणिपुर, 7 उत्तर प्रदेश और दो हिमाचल प्रदेश के हैं। विद्युतीकरण प्रक्रिया की प्रगति का http://garv.gov.in/dashboard पर भी पता लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र को दिए संबोधन पर अमल करते हुए भारत सरकार ने 1000 दिन के भीतर यानी 01 मई 2018 तक शेष 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण करने का फैसला किया है। इस परियोजना को अभियान के रूप में शुरू किया गया है और विद्युतीकरण के कार्यान्वयन का कार्य 12 महीने में पूरा किया जाएगा। इसके लिए गांवों के विद्युतीकरण की प्रक्रियाओं को निश्चित समयावधि में पूरा करने के लिए निगरानी हेतु 12 स्तरों पर विभाजित किया गया है।

अभी तक 7,549 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। शेष बचे 10,903 गांवों में से 444 गांव गैर-आबाद (निर्जन) हैं। 7,059 गांवों को ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है। भौगोलिक बाधाओं के कारण 3,003 गांवों का ऑफ ग्रिड के जरिए विद्युतीकरण किया जाएगा और 397 गांवों में विद्युतीकरण स्वयं राज्य सरकार करेगी। अप्रैल 2015 से 14 अगस्त 2015 के दौरान कुल 1654 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और भारत सरकार द्वारा इसे अभियान के तौर पर लेने के बाद 15 अगस्त 2015 से 01 मई 2016 तक अतिरिक्त 5895 गांवों में विद्युतीकरण किया गया है। ■

एकात्म मानववाद : एक अध्ययन

✍ पी. परमेश्वरन

एकात्म मानववाद भाजपा का मूल दर्शन है। वर्तमान समय में साम्यवाद और समाजवाद के विकल्प के रूप में एकात्म मानववाद सभी समस्याओं के हल का मार्ग बताता है। हम यहां विवेकानंद केन्द्र के अध्यक्ष एवं चिंतक श्री पी.परमेश्वरन का एक महत्वपूर्ण आलेख प्रकाशित कर रहे हैं। प्रस्तुत है प्रथम भाग :-

एकात्म मानवतावाद चुनावी सफलता के लिए एक त्वरित समाधान नहीं है और न ही यह सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक सुविधाजनक रणनीति है। यह किसी राजनीतिक दल को प्रोत्साहन या समर्थन देने के लिए तैयार की गई कोई युक्ति भी नहीं है। यह एक व्यापक वैश्विक- दृष्टि है, जिसका जन्म भारत के बुद्धिमान पुरुषों की पीढ़ियों की गहन अंतर्दृष्टि के परिणामस्वरूप हुआ, जिन्हें 'ऋषि' के रूप में जाना जाता हैं । इसमें मानव जीवन का हर पहलू शामिल है और इसकी नींव अनंतकाल के लिए मजबूत और हमेशा प्रासंगिक हैं। यह वही समृद्ध दर्शन है जिससे महान भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है। कोई भी सही मायने में राष्ट्रवादी आंदोलन सभी को समाविष्ट करने वाले इस दर्शन से लाभ प्राप्त कर सकता है। इसमें आध्यात्मिकता के साथ-साथ मानवता की भौतिक प्रगति भी समाहित है।

अपने वर्तमान स्वरूप में इस दर्शन को स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा श्री गुरूजी और दत्तोपंत ठेंगड़ी जैसे सहयोगियों के मार्गदर्शन में प्रतिपादित और हमारे लिए प्रस्तुत किया गया था। लेकिन वह इसे किसी खास समूह या संगठन की अनन्य संपत्ति नहीं बना देता है। यह एक बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है, जिसमें से भारत में प्रत्येक राष्ट्रवादी आंदोलन, राजनीतिक या गैर राजनीतिक प्रेरणा प्राप्त कर सकता है तथा एक रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य योजना के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्य से राजनीतिक दलों में से अधिकांश तथा कई सामाजिक और आर्थिक नीतियों और संस्थाओं ने हमारे देश के भीतर से अपने ताकत के स्रोत की तलाश करने की परवाह नहीं की, लेकिन आँख बंद करके विदेशों से उधार ले लिया। यही स्वतंत्र भारत का दुर्भाग्य है। वैश्वीकरण ने इस खतरनाक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। यहाँ एकात्म मानवतावाद विशेष रूप से प्रासंगिक और खास उपयुक्त हो जाता है। इसको देश की सभी बीमारियों के लिए रामबाण - 'संजीवनी' कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जुटकर खेती करने से यह 'कल्पतरु' बन जाएगा जो ''परम वैभव'' के फल देगा।

एक बार, जब ठेंगड़ीजी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ एकात्म मानववाद पर चर्चा कर रहे थे, श्रोताओं में से एक ने एक सवाल उठाया। उसने कहा "विचारधारा बहुत गहरी और निर्दोष है, लेकिन इसे समझना मुश्किल है और लागू करना और भी अधिक मुश्किल है। क्या आप कुछ और अधिक सरल और अभ्यास में आसान सुझा सकते हैं?" ठेंगड़ीजी ने जवाब दिया, "जब लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कोई अन्य तरीका नहीं है, तो सबसे लंबा रास्ता भी सबसे छोटा रास्ता ही है, अन्य कोई छोटा रास्ता आपको ही छोटा कर देगा"। वहाँ एक आश्चर्यजनक ठहराव आ गया था। यह अभी भी जारी है। मेरा मानना है कि उस ठहराव को तोड़ने और आगे बढ़ने के लिए यह एक गंभीर प्रयास है।

परिचय

मौजूदा वैश्विक प्रतिमान जो कि मूल रूप से पश्चिमी (अमेरिकी) है इसकी नींव और अस्थिरता की कमजोरी और अनिरंतरता के कारण अपने भीतर ही ढह रहा है। इस पर बाह्य बलों द्वारा भी हमला किया जा रहा है। दुनिया निराशापूर्वक एक अलग प्रतिमान की तलाश में है जो टिकाऊ और सभी के लिए उचित, दोनों हो।

पिछली सदी की अंतिम तिमाही के दौरान एक 'तीसरे विकल्प' के बारे में चर्चाएँ थी। एक गहन चिंतक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ीजी ने एक पुस्तक लिखी थी 'तीसरा मार्ग'। यह वही समय था जब पूंजीवादी और साम्यवादी दो प्रमुख प्रतिमान विश्व-नेतृत्व का दावा कर रहे थे। दोनों मूल रूप से पश्चिमी थे हालांकि परस्पर विरोधी विचारधाराओं पर आधारित

थे। लेकिन साम्यवादी प्रतिमान अपने खुद के गढ़ में ही ध्वस्त हो गया, पूंजीवाद विजयी हुआ और इसके गढ़ संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं को पूरी मानवता के लिए एकमात्र सफल प्रतिमान के रूप में प्रदर्शित करते हुए एक नई विश्व व्यवस्था को पुन: आकार देने के लिए एकाधिकार का दावा किया। लेकिन जश्न लंबे समय तक नहीं चल सका। हाल ही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ढहने, एक गुब्बारे की तरह फटने ने केवल अमेरिका के भीतर ही नहीं, बल्कि दुनिया के उन देशों में भी जिन्होंने विभिन्न स्तरों तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण कर लिया था, उन सभी देशों को हिला रख दिया। विकास के एक अलग प्रतिमान के वास्तुकार, फिदेल कास्त्रो ने अब खुलकर स्वीकार किया है कि क्यूबा का मॉडल पूरी तरह से विफल रहा है। यूरोप के देश - एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से में औपनिवेशिक बस्तियां बनाने वाले, तत्कालीन शाही स्वामी, बुरी तरह से पीछे रह गए हैं।

पूरी दुनिया पर छाई अराजकता की स्थितियों पर विचार करते हुए विश्व को एक नए प्रतिमान की आवश्यकता है। हमें जिसकी जरूरत है, वह वैकल्पिक प्रतिमान नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर प्रासंगिक और जीवन की दृष्टि पर आधारित एक 'सच्चा प्रतिमान' हो। कोई प्रतिमान जो वास्तविकता की दृष्टि को पहले से स्वीकार करता है, एक विश्व व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित करता है। दूरदर्शिता दृष्टि चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। वर्तमान अराजक, संघर्षात्मक, शोषक, धमकी भरा परिदृश्य चेतना के स्तर का एक सच्चा प्रतिबिंब है, जिस पर दुनिया का नेतृत्व संचालित होता है। वे इससे बेहतर नहीं हो सकते। सभी मशीनरी, सभी परिष्कृत यंत्रविन्यास, सभी आर्थिक और राजनीतिक उपकरण, और सभी सांस्कृतिक और सभ्यतागत संरचनाएँ, जो उन्होंने शुरू की हैं, वे सब इसी चेतना के उत्पाद हैं। एक वैकल्पिक प्रतिमान पाने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि चेतना का स्तर जिस पर उनका वैचारिक ढांचा कार्य करता है, उसमें तद्नुसार परिवर्तन होना चाहिए।

पश्चिमी संकल्पनात्मक ढाँचा, चाहे पूंजीवादी या साम्प्रदायिक, मूल रूप से भौतिकवादी है, जो परिवर्तन वे भौतिक स्तर पर लाना चाहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य मानवीय और प्राकृतिक दोनों संसाधनों को पुनर्व्यवस्थित करके एक 'आदर्श' प्रतिमान को आकार देना है। हरेक मायने में विकास और मानव कल्याण की अवधारणा को भौतिक मानकों के संदर्भ में मापा जाता है। आवश्यकताएँ, आराम और विलासिता सभी उस परिवर्तनशील भौतिक संपत्ति की सीमा की ओर संकेत करते हैं। मनुष्य भी, जिस पर सारे विकास कार्यक्रम लक्षित हैं, उनके अनुसार, एक भौतिक वस्तु है शरीर ही जिसका मुख्य आधार है। यह मनुष्य का एक अत्यधिक आंशिक और संकीर्ण दृश्य है। आनंद तथा माल और सेवाओं की एक भौतिक रूप से संतोषजनक आपूर्ति को ही वे लक्षित करते हैं। पूरी प्रक्रिया में वे उस आदमी की, जो एक उन्नत जानवर से कहीं ज्यादा है, पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं। सत्य के बारे में पश्चिमी दृष्टि की वास्तविक सच यही है। वे परस्पर विरोधी हितों के साथ एक अलग-अलग खानों में बँटी दुनिया देखते हैं।

I

दुनिया भर में एक आम सहमति है कि मानवता एक सभ्यतागत संकट का सामना कर रही है। कई प्रमुख विचारक इसे एक अस्तित्व का संकट मानते हैं, जिसे अगर तुरंत टाला नहीं गया तो मानव प्रजाति का विनाश भी हो सकता है, लेकिन यह जागरूकता केवल तार्किक या बौद्धिक स्तर पर ही है। यह पर्याप्त रूप से रिसकर भावनात्मक आयाम में नहीं पहुँची है जिसका परिणाम यह है कि यद्यपि विचार-विमर्श और बहस तो खूब होती हैं, लेकिन उनका किसी पर्याप्त परिचालन कार्यसूची से मिलान नहीं किया जाता। जब इसकी बात आती है तो दृष्टिकोण का एकमत रास्ता नहीं है। कानकुन सम्मेलन इस बात का प्रमाण है। निर्णय स्थगित कर दिए जाते हैं और जिन्हें चालू भी किया जाता है कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता।

यह भी स्वीकार किया गया है कि विकट संकट, मुख्य रूप से दुनिया की अकेली महाशक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुवाई में आक्रामक पश्चिमी सभ्यतापरक प्रतिमान का परिणाम है। इतना तो यूरोपीय देशों में भी स्वीकार किया गया है। अमेरिकन मॉडल मूल रूप से और अनिवार्यत: भौतिकवादी और उपभोक्तावादी है। इसकी जड़ें यहोवा द्वारा बाइबिल के आदेश में हैं कि प्रकृति मनुष्य द्वारा अपने आराम के लिए दोहन किए जाने के लिए है। साम्यवादी मॉडल पूंजीवाद की बीमारियों के लिए एक उपयुक्त समाधान विकसित करने में सफल नहीं हुआ है, जिसका मुख्य कारण यह है कि वह भी उतना ही भौतिकवादी है। यह ईसाइयत का एक अन्य संस्करण है जिसे उल्टा कर दिया गया है। यह पूँजीवाद की जड़ से उत्पन्न केवल एक प्रतिक्रियावादी फल है।

...क्रमश:

श्रद्धांजलि

जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक नहीं रहे

भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष श्री बलराज मधोक नहीं रहे। 2 मई 2016 को 96 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वे राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन के आधारस्तंभ थे, इसके साथ ही वे विचारक, इतिहासवेत्ता एवं लेखक भी थे। वे बेबाक अपने विचार व्यक्त किया करते थे। संसद में वे राष्ट्रीय विचारों के प्रथम प्रवक्ता रहे। साठ के दशक में अपनी सक्रियता से उन्होंने अपार ख्याति अर्जित की।

उन्होंने अपनी पुस्तक 'Indianisation' (भारतीयकरण) के माध्यम से बौद्धिक जगत में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। उनके ही अध्यक्षीय काल में भारतीय जनसंघ चरमोत्कर्ष पर पहुंची और पार्टी ने 1967 के लोकसभा चुनाव में अपना अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन किया।

श्री बलराज मधोक का जन्म कश्मीर के अस्कर्दू में 25 फरवरी 1920 में हुआ था। उनका बचपन गुजरांवाला (अब पाकिस्तान) में गुजरा। उन्होंने जम्मू, श्रीनगर और लाहौर में पढ़ाई की। उनकी उच्च शिक्षा लाहौर विश्वविद्यालय में हुई। 18 वर्ष की आयु में अपने छात्र जीवन में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में आये। सन 1942 में भारतीय सेना में सेवा (कमीशन) का प्रस्ताव ठुकराते हुए उन्होंने रा. स्व. संघ के प्रचारक के रूप में देश की सेवा करने का व्रत लिया।

उन्हें कश्मीर में संघ की शाखा प्रारंभ करने के लिए कश्मीर भेजा गया। उन्होंने 'जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद' के गठन में सहयोग किया। 1948 में वह दिल्ली चले आए और यहां उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

श्री बलराज मधोक 1951 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। वे संसद (लोकसभा) के दो बार सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1966-67 में वह भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। 1967 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने 35 सीटें जीती जो उस समय तक का पार्टी का सबसे बेहतरीन चुनावी प्रदर्शन था। पंजाब व उत्तर प्रदेश में जनसंघ की संयुक्त सरकारें बनी और देश के 8 प्रमुख राज्यों में जनसंघ मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरा था। वैचारिक मतभेद के चलते 1973 में बलराज मधोक को भारतीय जनसंघ से मुक्त कर दिया गया, लेकिन वे अन्य किसी राजनीतिक दल में नहीं गए।

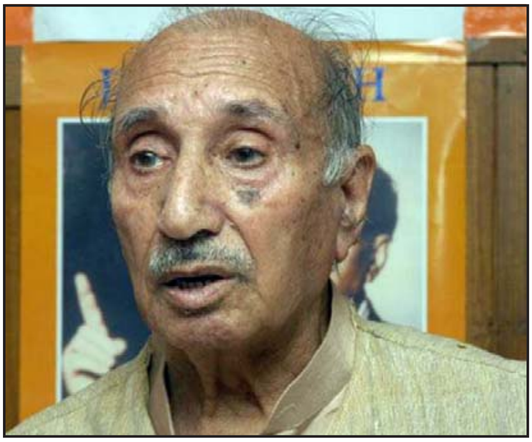

देश पर जब आपातकाल थोपा गया तो उन्होंने इसके विरुद्ध जमकर संघर्ष किया। इस दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया। जब आपातकाल हटा, तब वह जनता पार्टी में शामिल हुए और जनसंघ का इसमें विलय हो गया। 1979 में जनता पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने जनसंघ को अखिल भारतीय जनसंघ का नया नाम देकर पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। श्री बलराज मधोक की 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। ■

शोक संदेश

बलराज मधोकजी की विचारधारात्मक प्रतिबद्धता मजबूत और उनके विचार सुलझे हुए थे। साथ ही वे राष्ट्र और समाज के प्रति नि:स्वार्थ भाव से समर्पित थे।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

बलराज मधोकजी की मृत्यु पर गहरा आघात लगा है। उनका संपूर्ण जीवन देश व विचारधारा के प्रति समर्पित था। उनके परिवारजनों को सांत्वना।

अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

अगस्ता रिश्वत के तार कहां तक?

– बलबीर पुंज

अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में परत-दर-परत हो रहे खुलासे और संसद के भीतर और बाहर जारी आरोप-प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कथन, कि वह खुद को निशाना बनाए जाने से खुश है, कई प्रश्नों को जन्म देता है। आखिर क्यों राहुल गांधी को लगता है कि इस जांच के कारण वह निशाने पर आ गए है? क्या उनका यह बयान, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे को प्रासंगिक बनाता है?

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले को लेकर इटली की अदालत का जो निर्णय आया, उसने यह सिद्ध कर दिया कि भ्रष्टाचार के परिप्रेक्ष्य में यूपीए शासनकाल में ब्रह्मांड के किसी भी स्थान को नहीं छोड़ा गया। चाहे पताल लोक में कोयले का गोलमाल हो, धरती पर जमीन सौदों में भारी अनियमितता हो और अब आसमान में अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील में घोटाला।

इस घोटाले की आंच में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायण तक आ चुके हैं। जब इटली की 'मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स' में रिश्वत देने की बात सिद्ध हो चुकी है और इसे देने वाले फिनमैक्कैनिका कंपनी के पूर्व प्रमुख ज्यूसेप ओरसी और अगस्ता वेस्टलैंड की चॉपर डिविजन के प्रमुख ब्रूनो स्पैगनोलिनी जेल भेजे जा चुके हैं, तो प्रश्न उठता है कि भारत में घूस किसने ली? यह भी प्रश्न है कि क्या कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और यूपीए सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के सहमति के बिना यह सौदा संभव था?

> **भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि जो नाम अदालत के फैसले में जिक्र हुए है, वह निरपराध है। उस पश्चात इटली में मामले पर फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश मार्को मैगा का बयान टीवी चैनलों पर प्रसारित हुआ है। वास्तव में इटली में जांच उन इतालवी नागरिकों के खिलाफ थी, जो रिश्वत देने के आरोपी थे। उनपर आरोप भी सिद्ध हुआ और न्यायालय द्वारा दंडित भी किया गया। अब क्योंकि रिश्वत लेने वाले स्वाभाविक रूप से भारतीय थे और वह इटली की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, इसलिए उनपर न तो कोई निर्णय हुआ और न ही कोई सजा सुनाई गई। न्यायाधीश मैगा के अनुसार, "क्योंकि रिश्वत त्यागी बंधुओं के अलावा अन्य लोगों को भी बांटी गई थी, तो यह भारत पर निर्भर है कि वह जांच को आगे बढ़ाए।"**

अगस्ता घोटाले में राहुल गांधी को लेकर बीजेपी सांसद किरीट सोमैया का आरोप है कि घोटाले में एक बिचौलिया माइकल हेश्के एम्मार एमजीएफ कंपनी में निदेशक था और यह कंपनी राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार कनिष्क सिंह के परिवार की है और इसमें हेश्के का बतौर निदेशक होना कई प्रश्नों को जन्म देता है। क्या हेश्के और राहुल गांधी के बीच कोई संबंध रहा हैं?

इटली की अदालत के अनुसार 3,600 करोड़ का ठेका पाने के लिए इटली की कंपनी ने कुल रिश्वत की रकम से भारत के कुछ 'सक्षम' लोगों को कई सौ करोड़ रुपये की घूस दी। इस घोटाले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष शशिंद्रपाल त्यागी और त्यागी बंधुओं सहित गौतम खेतान का भी नाम सामने आ रहा है। परंतु क्या ये लोग इतने व्यापक सौदे का संचालन या इससे संबंधित निर्णयों में परिवर्तन करने में सक्षम थे? नहीं, क्योंकि जिस समय यानी साल 2010 में करार को अंतिम रूप दिया गया, उस समय एस.पी. त्यागी वायुसेनाध्यक्ष नहीं थे। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2004 से शुरू होकर 31 मार्च 2007 को खत्म हो चुका था, इस संदर्भ में साल 2007 के पश्चात उनकी डील में कोई भूमिका नहीं थी। सौदे को अंतिम रूप यूपीए-2 में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे "सक्षम" व्यक्तियों ने दिया था। प्रश्न है कि वह कौन से राजनेता या मंत्री थे, जिन्होंने सौदे से संबंधित नियमों और शर्तों में परिवर्तन कर, उसे केवल अगस्ता वेस्टलैंड के लिए यथोचित बनाया।

अगस्ता घोटाले में ब्रिटिश नागरिक क्रिस्चियन मिशेल की भूमिका महत्वपूर्ण है। कंपनी ने मिशेल को ही रिश्वत की सारी रकम सौंपी थी, जिसने उसे भारतीय बिचौलियों तक पहुंचाया, यह बात इटली की अदालत में सिद्ध भी हो चुकी है। क्रिस्चियन मिशेल और उसके पिता के भारत में कांग्रेस से शक्तिशाली राजनीतिक संपर्क थे, जिसका उसने डील में भरपूर

उपयोग किया।

इटली के अदालत के फैसले में मिशेल द्वारा 15 मार्च 2008 को लिखे एक पत्र का भी प्रसंग है, जिसे इटली की एजेंसियों द्वारा अभिग्रहण किया गया था। इस पत्र में लिखा है कि "सिग्नोरा गांधी इस सौदे के पीछे प्रमुख संचालक शक्ति हैं"। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह सिग्नोरा कौन है, जिसका उपनाम गांधी है? अदालत के फैसले में घूसकांड के मुख्य आरोपी ज्यूसेप ओरसी द्वारा लिखे एक पर्चे का भी हवाला दिया है। जुलाई 2013 का ये नोट ओरसी ने जेल से ही लिखा था।

नोट में ओरसी ने अपने लोगों से तत्कालीन इटली के प्रधानमंत्री मारियो मोंटी को भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात करने को कहा था। अदालत के फैसले में लिखा है कि ओरसी चाहता था कि भारतीय जांच एजेंसियां इटली की एजेंसियों के साथ जांच में सहयोग ना करें। अब क्या यही कारण था कि यूपीए शासन में इस मामले में ठोस जांच नहीं की गई? बुधवार को संसद में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी कहा कि साल 2012 को अगस्ता मामले में केस दर्ज होने के बाद क्यों सीबीआई और ईडी को जांच से रोका गया। पर्रिकर के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई "अदृश्य" हाथ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई का मार्गदर्शन कर रहा था। इटली के समाचारपत्रों ने भी यूपीए सरकार की नीयत पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए है। उनके अनुसार यूपीए शासन में सीबीआई ने दवाब में एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन जांच शुरू नहीं की और ईडी को नौ महीने तक एफआईआर की प्रति नहीं सौंपी। क्यों? मोदी सरकार बनने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की।

साल 2010 में देश के अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए इटली की अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 3,600 करोड़ रुपयों में करार किया गया। आरोप है कि साल 2005 के बाद, जिस समय यूपीए-1 सत्ता में थी, ऐसी परिस्थितियां बनाई गई, जिससे अगस्ता वेस्टलैंड ही सौदे में एकमात्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत हो सके। सौदे के दौरान असामान्य रूप से बदलावों को स्वीकृति दी और शर्तो में परिवर्तन कर सौदे को ऊंची दर पर तय किया गया, जिससे करार की कीमत 6 गुना बढ़ गई।

बुधवार को संसद में सरकार द्वारा मनोनित सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि साल 1998 में एनडीए शासनकाल में 6 एमआई-8 पुराने हेलिकॉप्टर की जगह 8 नए हेलिकॉप्टर खरीदने की चर्चा थी। उस समय हेलिकॉप्टर की उड़ान की ऊंचाई सुरक्षा हेतु 6,000 मीटर तक ले जाने की बात कही गई। परंतु यूपीए-1 कार्यकाल में इसे 4,500 मीटर कर दिया। अगस्ता के हेलिकॉप्टर ए.डब्ल्यू 101 को चुनने तथा इसके प्रतिद्वंद्वियों को दौड़ से बाहर करने के लिए कैबिन की 1.8 मीटर की उंचाई के मानदंड को अनिवार्य बनाया गया, जबकि यह शुरूआती शर्तो में 1.45 मीटर था। स्वामी के अनुसार जब पूर्व में 8 नए हेलिकॉप्टर को खरीदने की योजना थी, तो ऐसा क्या हुआ कि अगस्ता कंपनी के हेलिकॉप्टर की संख्या बढ़ा दी गई।

इटली के अखबारों के हवाले से एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि अगस्ता वेस्टलैंड से भारत द्वारा हेलिकॉप्टर उसकी वास्तविक मूल्यों से तीन गुना अधिक दाम पर खरीदे जा रहे थे। अखबारों में प्रकाशित समाचार के अनुसार एक हेलिकॉप्टर की कीमत 100 करोड़ थी, जिसे कंपनी द्वारा 300 करोड़ रुपये बताया जा रहा था। शुरुआत में कंपनी ने 12 हेलिकॉप्टर का आधार मूल्य 4,800 करोड़ रखा, परंतु उसने भारत को 3,600 करोड़ रुपये में इसे बेचने का प्रस्ताव दिया, जिसे तत्कालीन यूपीए सरकार ने बिना किसी जांच के स्वीकार भी कर लिया, यानी जो सौदा 1,200 करोड़ में संभव था, उसके लिए यूपीए सरकार 3,600 करोड़ रुपये देने को तैयार हो गई। क्यों?

स्वाभाविक रूप से अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले से स्वर्गीय राजीव गांधी के शासनकाल में हुए बोफोर्स घोटाले की याद ताजा हो जाती है। बोफोर्स में जिन लोगों ने घूस ली, उनकी पहचान तो हो गई। परंतु उचित जांच और साक्ष्य के आभाव में अदालत द्वारा किसी भी आरोपी को सजा नहीं हो पाई। प्रश्न है कि क्या यह घोटाला भी बोफोर्स की तर्ज पर बिना किसी तार्किक परिणति के इतिहास के गर्त में समा जाएगा। शायद नहीं, क्योंकि बोफोर्स घोटाले की जांच का जिम्मा साल 1989 में निर्वाचित वी.पी. सिंह सरकार के पास था, लेकिन अगले साल ही यह सरकार गिर गई। अब केंद्र में एक स्थिर सरकार है और वह भ्रष्टाचार को सामूल रूप से नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। आम नागरिकों की स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोटाले में लिप्त राजनेताओं और अफसरों को जल्द बेनकाब किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हे दंडित किया जाए। ■

साभार: नया इंडिया

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव-प्रचार

'डीएमके और एआईडीएमके की सरकारों ने भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं किया है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री अमित शाह ने 4 मई को तमिलनाडु के पट्टुकोट्टई, तेनकासी और नागरकोइल की रैली को संबोधित करते हुए तमिलनाडु की बदहाली के लिए डीएमके, एआईएडीएमके और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और उन पर जमकर प्रहार किया। साथ ही, उन्होंने राज्य की जनता से तमिलनाडु को विकास पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रदेश में भाजपा गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2016 के विधान सभा चुनाव में तमिलनाडु की जनता को यह निर्णय लेना है कि राज्य में विकास की धारा बहाने वाली भाजपा-नीत एनडीए की सरकार चाहिए या फिर भ्रष्टाचार और घोटाले वाली डीएमके और एआईएडीएमके की सरकार? उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में डीएमके और एआईएडीएमके - इन दोनों पार्टियों ने बारी-बारी से तमिलनाडु की जनता का शोषण किया है और भ्रष्टाचार का पोषण किया है, जबकि राज्य की जनता दोनों पार्टियों को सिरे से नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि डीएमके और एआईडीएमके की सरकारों ने पिछले 50 वर्षों से भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि डीएमके और एआईएडीएमके में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही करप्ट हैं और दोनों ने ही तमिलनाडु की जनता को विकास से महरूम रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण ही तमिलनाडु में बेरोजगारी, पीने के पानी और बिजली की समस्या है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में केंद्र में भाजपा की अगुआई वाली एनडीए सरकार के गठन के बाद से देश ने पहली बार विकास की राह पकड़ी है और देश के आम लोगों में आशा की एक नई किरण जगी है। उन्होंने कहा कि हमें यही शुरुआत तमिलनाडु में भी करनी है और इसके लिए राज्य में बारी-बारी से बननेवाली डीएमके और एआईएडीएमके की सरकारों को बदलकर भाजपा की अगुआई में एनडीए की सरकार बनानी है।

श्री शाह ने कहा कि तमिलनाडु उद्यमशीलता, मेहनत और उद्योगों की जगह भ्रष्टाचार का प्रतीक बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि डीएमके, एआईएडीएमके और कांग्रेस - तीनों पार्टियां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि टूजी, एयरटेल-मैक्सिस घोटाले के तार सीधे डीएमके और

कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के तमिलनाडु में चेहरा पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पहले से ही आय से अधिक संपत्ति के मामले और भ्रष्टाचार के कई अन्य मामलों में आरोपित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के यूपीए शासन में 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला किया - टूजी, कॉमनवेल्थ, हेलीकॉप्टर, कोल जैसे कई घोटाले यूपीए सरकार की तो झलकियां भर है। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके सुप्रीमो भी आय से अधिक संपत्ति, शराब घोटाले और कई अन्य घोटालों में संलिप्त रही हैं। उन्होंने कहा कि देश में कई प्रकार के घोटाले हुए पर तमिलनाडु में तो बच्चों के पीने वाले दूध में भी राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं द्वारा घोटाला किया गया। इतना ही नहीं, डीएमके और एआईएडीएमके, दोनों पार्टियों द्वारा 2000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के रेत और अवैध खनन के घोटाले हुए। श्री शाह ने तमिलनाडु की जयललिता सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब प्रदेश में एआईएडीएमके की पांच वर्षों के लिए सरकार बनती है तो लोगों को लगता है कि पता ही नहीं, कब मुख्यमंत्री बदल जाए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 50 वर्षों से तमिलनाडु ने दो पार्टियों और दो परिवारों का शासन देखा है, इससे मुक्ति पाने का एक अवसर 2016 के विधान सभा चुनाव है।

श्री शाह ने कहा कि केंद्र में 2 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्त्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने देश में भ्रष्टाचार-मुक्त शासन व्यवस्था की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राज्य के मछुआरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के दो वर्षों के शासनकाल में एक भी तमिल मछुआरे की हत्या श्रीलंकन नेवी के द्वारा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने श्रीलंका में फांसी की सजा दिये जा चुके होने के बावजूद तमिलनाडु के मछुआरों के सकुशल वापसी सुनिश्चित की और राज्य के स्वाभिमान को अक्षुण्ण बनाये रखा। उन्होंने कहा कि जब तमिलनाडु में बाढ़ आई, तब यहां की सरकार तो सोई रही लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी खुद चेन्नई में आकर राहत कार्यों की समुचित व्यवस्था के लिए डटे रहे और प्रभावित लोगों के मदद के लिए तत्काल 2000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई। श्री शाह ने जयललिता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की जनता की सुविधाओं पर खर्च करने के बजाय अम्मा के हस्ताक्षरित चेक बांटे गए, इतना ही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा सस्ते मूल्य पर जो चावल राज्य सरकार को दी जा रही है, मुख्यमंत्री उसे भी अपने नाम से जनता तक पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की एआईएडीएमके सरकार केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण और लेड बल्बों के उपयोग की योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को गांवों तक पहुंचाने की योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना और गरीब लोगों की आत्मनिर्भरता के लिए शुरू की गई मुद्रा योजना इत्यादि योजनाओं को लागू करने में उदासीन रही है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीब जनता के स्वास्थ्य की भलाई के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 2019 तक देश के पांच करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलिंडर देने की योजना 'उज्ज्वला योजना' की शुरुआत की गई है लेकिन तमिलनाडु में यदि डीएमके और एआईएडीएमके की सरकारें रहीं तो ये योजनाएं आम जनता तक नहीं पहुंच पाएंगी।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यदि तमिलनाडु को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाना है तो राज्य में बारी-बारी से बननेवाली डीएमके और एआईएडीएमके की सरकारों के ट्रेंड को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में एनडीए की सरकार बनती है तो तमिलनाडु की अधिकतर समस्याओं का अपने-आप समाधान हो जाएगा। उन्होंने राज्य की जनता से तमिलनाडु को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में भाजपा गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। ■

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यदि तमिलनाडु को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाना है तो राज्य में बारी-बारी से बननेवाली डीएमके और एआईएडीएमके की सरकारों के ट्रेंड को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में एनडीए की सरकार बनती है तो तमिलनाडु की अधिकतर समस्याओं का अपने-आप समाधान हो जाएगा।

केरल विधानसभा चुनाव-प्रचार

कांग्रेस भ्रष्टाचार करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, कम्युनिस्ट हिंसा का अपना स्वभाव नहीं छोड़ते : नरेन्द्र मोदी

गत 8 मई को केरल के कासरगोड, कुट्टनाड और तिरुअनंतपुरम की रेली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कहा कि करप्शन के लिए केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्टों की जबर्दस्त जुगलबंदी है, दोनों ने तय कर लिया है कि पांच वर्षो तक एक गरीबों का हक लूटेगा तो पांच वर्षो तक दूसरा। दोनों ने यह भी तय कर लिया है कि वे एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे और जनता की गाढ़ी कमाई पर मौज उड़ाते रहेंगे। कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच जो राजनीतिक समीकरण है, यह पॉलिटिक्स ऑफ अडजस्टमेंट है, पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज है, पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन है। कांग्रेस के कथनी और करनी में परस्पर विरोधाभास झलकता है, उनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। कांग्रेस यहां पर तो लेफ्ट से लड़ती है, लेकिन कोलकाता में दोनों हाथ मिला लेते हैं। यह उनका असली चेहरा है। क्या ऐसे लोगों पर किसी को विश्वास करना चाहिए? ऐसे लोग आपकी और हमारी सभी का अपमान करते हैं।

कांग्रेस भ्रष्टाचार करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, कम्युनिस्ट हिंसा का अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। इन दोनों ने मिलकर केरल को तबाह करके रख दिया है।

देश की जनता में भ्रष्टाचार के प्रति जबर्दस्त गुस्सा है और इसी का परिणाम है कि 400 सीटों वाली कांग्रेस आज 40 सीटों पर सिमट कर रह गयी है।

दिल्ली में केरल के विकास के लिए कितनी ही योजनाएं क्यों न बनें, राज्य के विकास के लिए कितने ही रुपये क्यों न भेजे जाएं, केरल सरकार इन्हें जनता तक पहुंचने ही नहीं देती।

आज केरल की जनता पर 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है, पब्लिक अंडरटेकिंग इकाइयों की हालत मरणासन्न है, औसत बेरोजगारी दर देश के औसत की तुलना में तीन गुना ज्यादा है, जनजातीय आबादी में शिशु मृत्यु दर काफी अधिक है और केरल अपने कुल उपभोग का केवल 13 प्रतिशत खाद्यान्न ही पैदा कर पाता है, आखिर केरल की इन समस्याओं का जिम्मेदार कौन है? केरल की इस बदहाली का श्रेय कांग्रेस-नीत यूडीएफ और लेफ्ट की एलडीएफ सरकारों को जाता है। 70 वर्षो में कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मिलकर केरल को दोनों हाथों से लूटा है। केरल में गरीबों का हक मारने वाले सरकारों की विदाई का वक्त आ गया है।

इटली की कोर्ट कह रही है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद में रिश्वत खाई गई। अगस्ता मामले में जो लोग दोषी हैं, उन्हें सजा होनी चाहिए या नहीं? हेलीकॉप्टर घोटाले में चोरी करनेवालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कांग्रेस जब केंद्र में थी तब उसने कोयले, 2जी, 3जी और न जाने कितने 'जी' में पैसे खाए। केरल सरकार में उनसे भी बड़े दिग्गज बैठे हैं, उन्होंने (कांग्रेस) कोयले और 2जी से खाया था, इन्होंने तो सूरज से भी पैसे खा लिए। जब ये सरेआम तपते सूरज से चोरी कर सकते हैं तो अंधेरी रात में भला क्या नहीं कर सकते।

भ्रष्टाचार इस देश के विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या है, सबने यह

मान लिया है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति संभव नहीं है, देश में एक निराशा का माहौल बन गया है। दो साल हमारी सरकार के आये हुए हो गए, आज तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप हमारी सरकार पर नहीं लग पाया है।

हमने गैस कनेक्शन से भ्रष्टाचार खत्म किया, गरीबों की सब्सिडी को सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा कराने की योजना शुरू की गई और लगभग 21000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार को खत्म करने में सफलता पाई।

इसी तरह हमने यूरिया की कालाबाजारी को खत्म किया, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में होने वाले पदों की भर्ती में से इंटरव्यू खत्म कर इसमें होनेवाले भ्रष्टाचार के खात्मे में सफलता पाई।

अगर इरादे साफ हों, नीयत साफ हो और नीति स्पष्ट हो तो देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है। हमें अगर देश का सर्वांगीण और चहुंमुखी विकास विकास करना है तो देश से भ्रष्टाचार खत्म करना होगा।

केरल में चारों तरफ पानी है फिर भी लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। आजादी के बाद से लेकर केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट गठबंधन की ही सरकारें रही है, केंद्र में भी लगभग 50 वर्षो तक कांग्रेस ही सत्ता में रही, लेकिन फिर भी उन्हें आप तक पानी पहुंचाने की चिंता भी नहीं है। जो लोग आपको पीने का पानी तक नहीं दे पाये, क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए, मैं आपसे इसका जवाब सुनना चाहता हूं।

केरल में सरकारें तो बदलती रही, लेकिन केरल की जनता का भविष्य नहीं बदला। आप तय करिये, आपको सिर्फ सरकार बदलना है या भविष्य बदलना है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट – एक बार जब आप दोनों को घर भेज देंगें तब इन्हें पता चलेगा कि सरकार गरीबों के लिए होती है, खुद के लिए नहीं।

मेरे लिए पूरा हिन्दुस्तान एक है। केरल से हमारा एक भी एमपी नहीं है, लेकिन केरल मेरा है, केरल का सुख दु:ख मेरा है।

सबरीमाला हादसे के समय देश के तब के प्रधानमंत्री के पास राज्य की जनता का दु:ख-दर्द बांटने तक का समय नहीं था, आज आपका प्रधान सेवक आपके बीच आपके हर दु:ख-दर्द बांटने को खड़ा है।

जब मैं सऊदी अरब गया तो सबसे पहले केरल के मजदूरों से मिला, उनके साथ खाना खाया और मिलकर उनके सुख दु:ख बांटे, इसी तरह जब मैं आबूधाबी और दुबई गया, वहां भी केरल के लोगों से मिला, क्योंकि केरल मेरा अपना है। मौजूदा सरकार ने यहां के किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया। उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थीं, वहीं केंद्र की सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है।

केरल में हर होने वाले चुनाव ने राज्य की जनता को जाति और धर्म में बांटा, लेकिन मैं यह सब खत्म करने यहां आया हूं, हम सब मलयालवी हैं और हम सब मलयालवी मिलकर एक होकर चुनाव लड़े, ये माहौल बनना चाहिए, केरल का भाग्य जरूर बदलेगा।

केरल की जनता को राज्य का विकास चाहिए। इसके लिए ऐसी सरकार चाहिए जो यहां पर विकास की गति को तेज कर सके और बेरोजगारों को काम दे सके। यह केवल भाजपा की सरकार ही कर सकती है।

मेरी सरकार का एक ही मंत्र है 'सबका साथ, सबका विकास', हमारी सरकार का केवल एक ही मंत्र है- विकास, विकास और विकास।

पहले जहां भ्रष्टाचार और दंगों की राजनीति होती थी वहां अब विकास की राजनीति होने लगी है।

हम केरल के विकास के लिए वोट मांगने आये हैं, केरल को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए वोट मांगने आये हैं, हम केरल की समृद्धि और आम जनता के जीवन में बदलाव लाने के लिए राज्य की जनता से वोट मांगने आये हैं। यह चुनाव जीत-हार का नहीं है, यह चुनाव केरल के भविष्य का चुनाव है, यह केरल के नौजवानों, मछुआरों, किसानों, माताओं एवं बहनों के भविष्य का चुनाव है। ■

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव-प्रचार

'तमिलनाडु का भाग्य बदलने के लिए राज्य में भाजपा सरकार की जरूरत है'

तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कन्याकुमारी में पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। हमारी सरकार ने कन्याकुमारी के विकास के लिए केंद्र का खजाना खोल दिया है। कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम तक जल्द ही सड़क बनेगी, इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

यहां एक विकसित बंदरगाह का निर्माण होगा। यहां युवाओं के रोजगार के संभावनाओं की तलाश के लिए लगभग 21000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।

राज्य सरकारें भी जहां पहुंच नहीं पाती, केंद्र सरकार उससे पहले लोगों के मदद के लिए पहुंच जाती है। सरकार क्या होती है, कैसे काम करती है, देश यह पहली बार अनुभव कर रहा है।

हम तमिल के मछुआरों को कभी मरने नहीं देंगे। श्रीलंका में फांसी की सजा पा चुके पांच तमिल भाइयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित की, तालिबान के चंगुल से फादर प्रेम की सकुशल वापसी सुनिश्चित की और केरल की बेटियों को आतंकवादियों के कब्जे से छुड़ाकर सकुशल वापस भारत लाने में हम सफल हुए। तमिलनाडु का भाग्य बदलने के लिए, राज्य के लोगों के जीवन को बदलने के लिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की जरूरत है।■

पं. बंगाल विधानसभा चुनाव-प्रचार

मां, माटी और मानुष का नारा देनेवाली दीदी के राज में जनता भय, भूख और भ्रष्टाचार से त्राहिमाम है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री अमित शाह ने 27 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर, (साउथ 24 परगना) और भवानीपुर (कोलकाता दक्षिण) की रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की बदहाली के लिए कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों और तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर करारा प्रहार किया। साथ ही, उन्होंने राज्य की जनता से पश्चिम बंगाल के विकास के लिए तथा राज्य को भ्रष्टाचार, आतंक और घुसपैठ की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को चारों तरफ से घेरते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, चाहे वह हवा, पानी, जमीन या फिर पाताल ही क्यों न हो, जहां उसने भ्रष्टाचार का कोई कांड न किया हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में भी कांग्रेस के ही घोटाले एक-एक करके सामने आते थे और अब मोदी सरकार के दो वर्षों के शासनकाल में भी कांग्रेस के ही घोटाले एक-एक करके सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगस्टा वेस्टलैंड में पूरी तरह से फंस चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कम-से-कम कांग्रेस को तो इटली के कोर्ट के फैसले पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बहुत जल्द ही इस घोटाले की सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अगस्टा वेस्टलैंड घोटाला हो गया, लेकिन ममता दीदी इस पर कुछ बोल ही नहीं रही, आखिर वह चुप क्यों है? उन्होंने कहा कि वह इसलिए चुप हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं शारदा, नारदा और मालदा मामले में वह कहीं घिर न जाए। उन्होंने जनता को आगाह किया करते हुए कहा कि ममता दीदी का जवाब कम्युनिस्ट या कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकती, उनका जवाब केवल भारतीय जनता पार्टी ही हो सकती है। श्री शाह ने कहा कि शारदा मामले में 17.5 लाख परिवारों की गाढ़ी कमाई लूट ली गई, लेकिन दीदी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा कि आज राज्य की जनता तृणमूल कांग्रेस की सरकार से जवाब मांग रही है। श्री शाह ने कहा कि कोलकाता में हुआ विवेकानंद ब्रिज हादसा आज देश भर में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि नारदा में जिस तरह बेशर्मी का प्रदर्शन करते हुए तृणमूल के नेता सरेआम कैमरे पर गरीबों के पैसे लूटते हुए दिखाई दिए, वह अपने आप में तृणमूल सरकार की भ्रष्टाचार गाथा कहने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारविहीन शासन केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है।

कांग्रेस पर पलटवार करते हुए श्री शाह ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में बुद्धदेब भट्टाचार्य और राहुल गांधी एक मंच से मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं कल वह केरल में एक-दूसरे के खिलाफ जहर उगलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में दोस्ती और केरल में कुश्ती - यह समझ से बाहर की बात है। उन्होंने कहा कि यह समझ में ही नहीं आता कि यह सिद्धांतों की लड़ाई है या केवल किसी भी तरह सत्ता प्राप्त करने की साजिश? उन्होंने कहा कि किसी भी तरह सत्ता प्राप्त करना कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की परम्परा रही है।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां और तृणमूल कांग्रेस सब एक ही हैं। उन्होंने कहा कि नारदा घूसकांड के मामले को हमने लोक सभा में स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजा, लेकिन राज्य सभा में तीनों पार्टियां मिलकर इस मामले में अड़ंगा डाल दिया। उन्होंने कहा कि आज इन लोगों के चेहरे से नकाब उतर गया है। तृणमूल कांग्रेस को विवेकानंद ब्रिज हादसे में तृणमूल कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि यदि ब्रिज का ठेका वामपंथी पार्टियों के शासनकाल में शुरू हुआ था तो फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने ठेका रद्द क्यों नहीं किया, आखिर तृणमूल कांग्रेस की लेफ्ट पार्टियों से क्या सांठ-गांठ है? उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से भ्रष्टाचार और अपराध को समाप्त करने के लिए हमें तृणमूल कांग्रेस सरकार के

सिंडिकेट कल्चर को खत्म करना होगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एक समय था जब बंगाल विकास और समृद्धि में देश का नेतृत्त्व करता था, आजादी के समय पश्चिम बंगाल देश के कुल जीडीपी का 25 प्रतिशत कंट्रीब्यूट करता था, जबकि ममता बनर्जी की सरकार में यह 4 प्रतिशत पर आ गया है। उन्होंने कहा कि इन पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल में विकास के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसके ठीक उलट मां, माटी और मानुष का नारा देनेवाली दीदी के राज में जनता भय, भूख और भ्रष्टाचार से त्राहिमाम है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की समस्या पर बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या और गहराती जा रही है। उन्होंने कहा कि न कांग्रेस, कम्युनिस्ट और न ही तृणमूल कांग्रेस ही पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या पर अंकुश लगा सकती है, क्योंकि ये सब घुसपैठ को अपने-अपने वोट बैंक के नजरिये से देखते हैं। उन्होंने कहा कि इनके गलत नीतियों के कारण देश में सुरक्षा का एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बांग्लादेश के साथ लगने वाली राज्य की सीमा को सील किया जाएगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का गढ़ बन गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में केवल एक ही उद्योग फल-फूल रहा है और वह है - बम बनाने का उद्योग। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल सरकार चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रही है, विकास के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ वह कोई कदम नहीं उठा रही है और न ही अपराधियों पर नकेल ही कस रही है। उन्होंने कहा कि दीदी की नजर में भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनता की गाढ़ी कमाई के डूबने से ज्यादा चिंता उन्हें अपनी सत्ता की है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में केंद्र की भाजपा-नीत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों पर लगातार नकेल कस रही है और साथ ही उन्हें कानून के दायरे में लाकर उन्हें सजा दिलाने के लिए काम कर रही है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगाल का विकास करना चाहते हैं, लेकिन राज्य में एक ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र से कंधे-से-कंधा मिलाकर राज्य के विकास के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपया देती है, लेकिन ममता सरकार यह पैसा राज्य की जनता की भलाई के लिए खर्च ही नहीं करती। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा इस वर्ष का पेश किया गया बजट गांव, गरीब और किसानों का बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट बेरोजगारों के लिए आशा की किरण का बजट है। उन्होंने कहा कि पहली बार गांवों और कस्बों के विकास के लिए बजट में अलग से राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों की स्वास्थ्य चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक साल में 3000 से अधिक सस्ती दवाओं की दुकान खोलने का निश्चय किया है। श्री शाह ने कहा कि देश के गरीबों के लिए एक लाख करोड़ रुपये की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना मोदी सरकार का एक प्रशंसनीय कदम है। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किसानों को सुरक्षा कवच देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की, मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से देश के लाखों युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराई गई, जन-धन योजना के माध्यम से देश के करोड़ों गरीब परिवारों के बैंक खाते खोले गए और सहायता राशि को सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की व्यवस्था की गई, युवाओं को प्रशिक्षित कर उनके बेहतर भविष्य के लिए स्किल्ड इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार रहते इन योजनाओं का राज्य की जनता तक पहुंचना मुमकिन नहीं लगता।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि हम बंगाल की जनता के सामने एक विकल्प देने आये हैं। श्री शाह ने भवानीपुर विधानसभा की जनता से अपील करते हुए कहा कि देश के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी बेकार न जाने दें, भवानीपुर की जनता के पास वीर सुभाष को श्रद्धांजलि देने का अनुपम मौका है, आप ममता दीदी को हराकर केवल भवानीपुर में परिवर्तन कर दीजिए, पूरे पश्चिम बंगाल में अपने-आप परिवर्तन आ जाएगा। उन्होंने राज्य की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि हमें बंगाल में परिवर्तन लाने का निश्चय करना है और राज्य में विकास की बयार लाने के लिए भरतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि हम पश्चिम बंगाल के खोये हुए गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ■

गाजियाबाद (उप्र) में 'ग्राम उदय से भारत उदय' कार्यक्रम

'राज्य में सपा-बसपा की सरकारों का सिलसिला खत्म करना होगा'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 'ग्राम उदय से भारत उदय' अभियान के तहत आयोजित समारोह में पंचायत प्रधानों और ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से राज्य की भ्रष्टाचारी समाजवादी पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ कर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आहवान किया, साथ ही उन्होंने पिछले लोक सभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित सफलता के लिए राज्य की जनता के प्रति अपना हार्दिक आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में हम केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा देश के गांव, गरीब, युवा और किसानों की भलाई के लिए चलाये जा रहे सभी लोक-कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का 'ग्राम उदय से भारत उदय' का अभियान केवल नारा नहीं है, बल्कि यह देश के सर्वांगीण विकास के सपने को साकार करने का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि यदि हमें देश का सर्वसमावेशिक और चहुंमुखी विकास करना है तो गांवों का विकास आवश्यक है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने केंद्र के खजाने का मुंह गांवों की ओर खोल दिया है। उन्होंने कहा कि

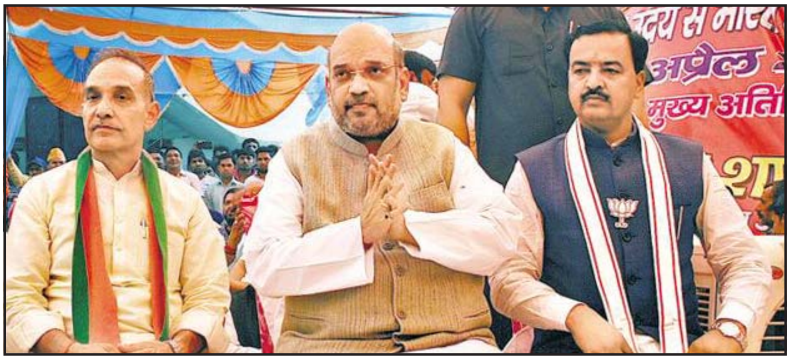

आजादी के बाद पहली बार देश में एक ऐसा बजट पेश किया गया है जिसका लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा गांवों के विकास पर खर्च किया जाएगा। पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यदि गांवों के विकास पर पहले से जोर दिया गया होता तो आज गांवों की ये हालत न होती। उन्होंने कहा कि गांवों की दशा और दिशा बदलने और हर गांव को एक आदर्श ग्राम बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने 'ग्राम उदय से भारत उदय' अभियान की शुरुआत की है और यदि पंच, सरपंच एवं भाजपा का हर कार्यकर्ता इस अभियान के लिए कमर कस ले तो गांवों की सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पहले गांवों और कस्बों के पास विकास के लिए अपना बजट नहीं होता था, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद गांवों और कस्बों के विकास के लिए अलग से कोष बनाया गया है और इस बार के बजट में हर गांव को विकास के लिए 80 लाख और हर कस्बे को 21 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश के किसानों को मुसीबतों से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने जो सहायता राशि राज्य सरकार को भेजी थी, वह अब भी किसानों तक नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने बारी-बारी से कई वर्षो तक शासन किया है पर राज्य अभी भी विकास में पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करना है तो उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा की सरकारों का सिलसिला खत्म करना होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य की जनता के लिए फैसला लेने का वक्त आ गया है और मुझे उत्तर प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है, वह इस बार राज्य में विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है।■

'आखिर किसके इशारे पर अगुस्ता वेस्टलैंड को टेंडर भरने की अनुमति दी गई'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अगुस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाले को लेकर कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले पर कांग्रेस पर तथ्यों की लीपापोती का आरोप लगाते हुए श्री शाह ने कहा कि इटली की कोर्ट में अगुस्ता-वेस्टलैंड डील में भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध होने के बाद भी कांग्रेस अपने नेताओं और यूपीए सरकार के मंत्रियों के तत्वाधान में अलग-अलग भ्रामक सवाल खड़े करके बस देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस मामले में भ्रष्टाचार के प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित करते हुए कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से चार महत्त्वपूर्ण सवाल पूछे और कांग्रेस अध्यक्षा से इन चारों सवालों पर स्पष्टीकरण देने की मांग की, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

पहला सवाल – श्री शाह ने कहा कि जब वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई, तो टेंडर के चैप्टर संख्या-2 के पैरा-2 में एक प्रावधान था कि टेंडर को ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफेक्चरर ही भर सकते हैं, इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने अगुस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटिड को न केवल टेंडर भरने की इजाजत दी, बल्कि उसे टेक्निकली क्वालीफाई भी कराया, जबकि अगुस्ता वेस्टलैंड के 2012 के रिपोर्ट में ही यह बात सार्वजनिक हो चुकी थी कि वह एक ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफेक्चरर नहीं है। भाजपा अध्यक्ष ने सोनिया गांधी से प्रश्न करते हुए पूछा कि आखिर किसके इशारे पर ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफेक्चरर नहीं रहने के बावजूद अगुस्ता वेस्टलैंड को टेंडर भरने की परमिशन दी गई, टेक्निकली क्वालीफाई कराया गया और टेंडर की शर्तों के साथ छेड़छाड़ की गई?

दूसरा सवाल – भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर अगुस्ता वेस्टलैंड के फील्ड इवोल्यूशन ट्रायल की शर्तों को बदलने का आरोप मढ़ते हुए कहा कि टेंडर के मुताबिक फील्ड इवोल्यूशन ट्रायल भारत में होना था, जबकि अगुस्ता वेस्टलैंड से समझौता होने के बाद फील्ड इवोल्यूशन ट्रायल की जगह को भारत से बदलकर कंपनी की प्रिमाइसेस की जगह पर कर दिया गया। श्री शाह ने कहा कि क्या ट्रायल की गम्भीरताओं के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, क्या भारत के हितों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई? उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि यदि फील्ड इवोल्यूशन ट्रायल क्लॉज को चेंज करने की परमिशन तत्कालीन रक्षा मंत्री ने दी थी तो आखिर उन्होंने ट्रायल की गम्भीरताओं के साथ कॉम्प्रोमाइज किसके इशारे पर किया, क्या वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं?

तीसरा सवाल – भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अगुस्ता वेस्टलैंड के साथ सौदा होने के कुछ दिनों के बाद ही इटली की मीडिया में इस सौदे में रिश्वत देने की बात सामने आ गई थी। उन्होंने एक गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जब टेंडर में ऐसा प्रोविजन था कि यदि ऐसा मामला बनता है तो सौदे को 'पुट ऑन होल्ड' कर दिया जाएगा तो फिर मीडिया में रिश्वत की बात आने के बाद भी सौदे को 'पुट ऑन होल्ड' क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि इस प्रोविजन का उपयोग किये बगैर टेंडर की प्रक्रिया को पूरा किया गया और जब इटली में रिश्वत देने वालों की धड़-पकड़ शुरू हुई एवं गिरफ्तारी हुई और यह सिद्ध हो गया कि इस सौदे में रिश्वत दी गई है, तब कहीं जाकर इस सौदे को 'पुट ऑन होल्ड' किया गया। उन्होंने पूछा कि आखिर इस प्रक्रिया में इतनी देर क्यों की गई और किसके इशारे पर की गई?

चौथा सवाल – भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का यह कहना कि बैंक गारंटी के तौर पर अगुस्ता वेस्टलैंड को दी गई सारी रकम कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने वापस ले ली थी, पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि इस रकम का बस एक ही हिस्सा यूपीए सरकार वापस ला पाई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा को इस झूठ पर भी सफाई देनी चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा को देश की जनता के सामने आकर सारे सवालों का जवाब देना चाहिए ताकि सच बाहर आ सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर 'उलटा चोर, कोतवाल को डांटें' वाली कहावत चरितार्थ होती है, उन्हें कुछ तो शर्म करनी चाहिए। ■

देश जानना चाहता है भ्रष्टाचार में कौन शामिल था : मनोहर पर्रिकर

गत 4 मई को राज्य सभा में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। श्री पर्रिकर ने कहा कि ए.के. एंटनी ने सौदे में भ्रष्टाचार होने की बात मानी थी। अब सवाल ये है कि घूस का पैसा किसे मिला? हम यहां उनके भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं :-

निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में पाई गई खामियों की सूची कदाचार तथा खरीद प्रक्रिया में भ्रष्ट कार्रवाई और स्वीकृत मानदंडों के उल्लंघन की ओर इंगित करती है। 5 अगस्त, 1999 को वायु सेना ने एमआई-8 वीआईपी हेलीकॉप्टरों को बदलने का प्रस्ताव रखा तथा 20 मार्च, 2002 को विश्व स्तर पर 11 विक्रेताओं को आरपीएफ जारी किया गया। तकनीकी मूल्यांकन समिति ने तीन विक्रेताओं अर्थात् एमआई-172, ईसी 225 तथा ईएच-101 एक के नाम का चयन किया। ईएच-101 के उड़ान का मूल्यांकन नहीं किया जा सका, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर 6,000 मीटर की ऊँचाई के लिए प्रमाणित नहीं किया गया था। ईएच-101 हेलीकॉप्टर का बाद में नाम बदलकर अगस्ता वेस्टलैण्ड का एडब्ल्यू-101 कर दिया गया। उड़ान मूल्यांकन के पश्चात् खरीद के लिए केवल ईसी 225 को ही उपयुक्त पाया गया। 2005 से तत्कालीन सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए, जिनके परिणामस्वरूप अंतत: एडब्ल्यू हेलीकॉप्टर की खरीद की गयी। इन कदमों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कड़ी आलोचना की। इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ था, इस तथ्य को मिलान हाई कोर्ट के हाल के निर्णय में विस्तार से उजागर किया गया है। देश यह जानना चाहता है कि भ्रष्टाचार को किसने प्रोत्साहित किया, किसने समर्थन दिया तथा इससे किसको लाभ पहुंचा।

हम इसे जाने नहीं दे सकते। संशोधित सेवा गुणवत्ता अपेक्षाओं में केबिन की ऊंचाई 1.8 मीटर अनिवार्य कर दी गई थी। 3 जनवरी, 2006 को रक्षा अर्जन परिषद् द्वारा 793 करोड़ रुपए के 12 हेलीकॉप्टरों की अधिप्राप्ति की आवश्यकता को स्वीकृत किया गया था। एस. क्यू. आर. में इन परिवर्तनों ने ईसी 225 हेलीकॉप्टर को मुकाबले से बाहर कर दिया, जो कि पहले प्रचालन अपेक्षाओं को पूरी करता था और ए. डब्ल्यू.-101 को इसमें शामिल कर दिया। इस प्रकार, कुछ प्रकार के हेलीकॉप्टरों तक ही विकल्प सीमित रह गए। जबकि आर. एफ. पी. मैसर्स अगस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को जारी की गई थी, लेकिन आर. एफ. पी. का उत्तर मैसर्स अगस्ता वेस्टलैण्ड इंटरनेशनल लिमिटेड, यूके से प्राप्त हुआ जो कि वह कंपनी नहीं थी, जिसे आर. एफ. पी. भी जारी की गई थी। मैसर्स अगस्ता वेस्टलैण्ड इंटरनेशनल लिमिटेड, यूके की बोली को सीधे-सीधे अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि यह वह कंपनी नहीं थी जिसे आर. एफ. पी. जारी की गई थी। इसके स्थान पर, ए. डब्ल्यू. आई. एल. के पक्ष में लगातार प्रयास किए जाते रहे। आर. एफ. पी. में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया था कि एफ. ई. टी. बिना किसी लागत और बिना किसी वचनबद्धता के आधार पर भारत में ही होगी। विदेश में परीक्षणों की अनुमति देकर इस महत्वपूर्ण पहलू की उपेक्षा की गई है। यहां तक कि परीक्षण भी निरूपक हेलीकॉप्टरों पर किया गया, क्योंकि एफ. ई. टी. के समय अगस्ता वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर विकास के चरण में था। एफ. ई. टी. में न तो एस-92 और न ही ए. डब्ल्यू-101 ने एस. क्यू. आर. की अपेक्षाओं को पूरा किया था। तथापि, दो मापदंडों की अनदेखी करते हुए और एक मात्र विक्रेता होने के बावजूद ए. डब्ल्यू.-101 को शामिल करने की सिफारिश की गई, जबकि एस-92 को ऐसी कोई रियायत नहीं दी गई। आर.

एफ. पी. की तीन वर्ष/900 घंटे, जो भी बाद में हो, की शर्त के स्थान पर मैसर्स ए. डब्ल्यू आई. एल. द्वारा संपूर्ण हेलीकॉप्टर पर तीन वर्ष/900 घंटे, जो भी पहले हो की वारंटी की पेशकश को स्वीकार किया गया। अधिप्राप्ति में स्वीकृत सिद्धांत यह है कि परिवर्तनों की केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगस्ता वेस्टलैण्ड ने इस ऑफसेट कार्यक्रम के अंतर्गत आई. डी. एस. इन्फोटेक द्वारा 2011 से 2014 तक किए जाने वाले कार्य का वर्षवार अलग-अलग ब्यौरा दिया गया, जबकि कार्य 2010 में संविदा खत्म होने से पहले ही पूरा हो गया था। इस मामले में अब तक हुई जांच से घूस की राशि के अंतरण के रूप में आईडीएस इन्फो टेक की लिप्तता का पता चला है। ऐसे हेलिकॉप्टरों का आधार मूल्य, प्रस्तुत मूल्य से कहीं ज्यादा था। यह मूल्य प्राक्कलित कुल परियोजना लागत से 6 गुना था, जो दर्शाता है कि समुचित प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कीमत को लेकर बातचीत करने के संबंध में सीएनसी ने कोई यथार्थ आधार नहीं बताया था।

अंतिम तय कीमत प्राक्कलित लागत से काफी ज्यादा थी। यहां तक कि कैग की रिपोर्ट में भी ऐसी खरीद में मानदंडों का पालन न करने की बात कही गई है।

भ्रष्टाचार संबंधी यह मामला फरवरी, 2012 से इटली की मीडिया में आना शुरु हुआ। भारत सरकार ने कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाए, विदेश मंत्रालय तथा दूतावास इत्यादि को पत्र लिखने का रास्ता अपनाया और कंपनी से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया और वह समझौता जारी रहा। यहां तक कि दिसम्बर, 2012 में तीन हेलीकॉप्टरों की डिलिवरी भी ले ली गई। मेसर्स फिनमेकानिका प्रमुख की गिरतारी की खबरें मिलने के बाद ही रक्षा मंत्रालय ने 12 फरवरी, 2013 को सीबीआई को इस मामले में जांच करने के लिए कहा।

15 फरवरी 2013 को पहला कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ समझौते का प्रचालन और किए जाने वाले भुगतान को रोक दिया गया। एजी की सलाह पर 1 जनवरी 2014 को इस करार को रद्द कर दिया गया और सभी गारंटी/बांड भुना लिए गए। हालांकि, मैसर्स एडब्ल्यूआईएल को किए गए 250.32 मिलियन यूरो के अग्रिम भुगतान में से केवल तीन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी संबंधी 199.62 मिलियन यूरो की राशि की वसूली ही की जा सकी। इसके अतिरिक्त सरकार को 398.21 मिलियन यूरो का अनुमानित नुकसान उठाना पड़ा। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि सीबीआई, जिसने इस संबंध में 12 मार्च, 2013 को एफआईआर दर्ज की थी, उसने नौ महीने तक इस एफआईआर की प्रति प्रवर्तन निदेशालय को भेजना जरूरी नहीं समझा। जुलाई, 2014 में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई नहीं की। ऐसा लगता है कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के कारोबार को कोई बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति निर्देशित कर रहा था। मौजूदा सरकार के आने के पश्चात् सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय तीन विदेशी नागरिकों की गिरतारी और/या प्रत्यावर्तन सहित जांच के सभी पक्षों की गहन छानबीन करते रहे और रक्षा मंत्रालय के पास निविदा को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

यदि तत्कालीन सरकार ने सही समय पर कार्रवाई की होती तो भुगतान की गई पूरी अग्रिम राशि वापस मिल गई होती। इस बात पर पूर्णतः सहमति है कि अगस्ता वेस्टलैण्ड हेलीकाप्टरों के प्रापण में भ्रष्टाचार हुआ था। इटली के न्यायालय ने भी अपने फैसले में इस बात को एक स्वर से स्वीकार किया है कि इस डील में भ्रष्टाचार हुआ था। अतः सबसे प्रमुख कार्रवाई यह होनी चाहिए कि इन भ्रष्ट आचरणों की पहचान की जाए। सीबीआई पहले ही काफी जांच कर चुकी है। मैं कुछ स्पष्ट कारणों से जांच का ब्यौरा नहीं दे सकता हूं। ■

यदि तत्कालीन सरकार ने सही समय पर कार्रवाई की होती तो भुगतान की गई पूरी अग्रिम राशि वापस मिल गई होती। इस बात पर पूर्णतः सहमति है कि अगस्ता वेस्टलैण्ड हेलीकाप्टरों के प्रापण में भ्रष्टाचार हुआ था। इटली के न्यायालय ने भी अपने फैसले में इस बात को एक स्वर से स्वीकार किया है कि इस डील में भ्रष्टाचार हुआ था। अतः सबसे प्रमुख कार्रवाई यह होनी चाहिए कि इन भ्रष्ट आचरणों की पहचान की जाए। सीबीआई पहले ही काफी जांच कर चुकी है। मैं कुछ स्पष्ट कारणों से जांच का ब्यौरा नहीं दे सकता हूं।

भारत स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व करेगा : पीयूष गोयल

बिजली, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने 29 अप्रैल को कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में भारत अब विश्व का अनुसरण नहीं, बल्कि नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि ग्रिड से कनेक्टिड 21 जीडब्ल्यू नई सौर परियोजनाओं के बाजार में उतरने के साथ ही भारत ने विश्व को संकेत दिया है कि वह अब छलांग लगाने को तैयार है। साथ ही उन्होंने सीएसटी और सोलर कुकर उत्कृष्टता पुरस्कार-2016 से सम्मानित 102 व्यक्तियों का अभिनंदन भी किया। श्री गोयल ने इस अवसर पर संकेंद्रित सौर तापीय प्रौद्योगिकी (सीएसटी) के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए कई विशेषज्ञों द्वारा मिलान किए गए 9 ज्ञान दस्तावेज भी जारी किए।

श्री गोयल ने कहा कि सौर कार्यक्रम हमारे देश में सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा को ही सुनिश्चित नहीं करेगा, बल्कि पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर मौजूद अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुंचाएगा। पुरस्कार विजेताओं की सराहना करते हुए श्री गोयल ने कहा कि ऐसी परियोजनाएं समग्र सौर लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

श्री गोयल ने दोहराया कि भारतीय सौर लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल हम अपने सौर लक्ष्यों को 116 प्रतिशत तक प्राप्त कर चुके हैं और 11000 मेगावॉट की परियोजनाएं पहले ही प्रदान कर चुके हैं। ये पुरस्कार राज्य नोडल एजेंसियों, प्रौद्योगिकी के विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं तथा लाभार्थियों की व्यापक रेंज सहित विभिन्न हितधारक समूहों को इस क्षेत्र में उनके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का अभिनंदन करने के लिए प्रदान किए गए हैं।

भारत-बांगलादेश के बीच चार मार्गों पर बस सेवाओं का परिचालन

वर्तमान में भारत और बांगलादेश के बीच चार मार्गो पर बस सेवाओं का परिचालन किया जा रहा है। इनमें शामिल हैं: 1-त्रिपुरा सड़क परिवहन निगम/पश्चिम बंगाल भूतल परिवहन निगम और बांगलादेश सड़क परिवहन निगम द्वारा आने जाने के लिए तीन बसों का परिचालन किया जाता है। इस सेवा की मदद से पारंपरिक सिलिगुडी-गुहावटी-सिल्चर मार्ग पर कोलकाता और अगरतला के बीच 1550 किलोमीटर की दूरी कम होकर नए मार्ग पर केवल 640 किलोमीटर रह गई है। 2-शिलांग होकर असम राज्य परिवहन निगम और बांगलादेश सड़क परिवहन निगम की आने जाने के लिए एक बस है। ये दोनों बस सेवाएं पिछले वर्ष जून में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा शुरू की गई थी। इनके अतिरिक्त पहले की दो बस सेवाएं भी है।

गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच यात्री बसों का परिचालन क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। भूटान और नेपाल के साथ ही भारत ने बांगलादेश से भी बीबीआईएम मोटर वाहन समझौता किया है। इसका उद्देश्य चारों देशों के बीच यात्रियों और माल वाहन परिवहन को नियमित करना तथा आपसी लाभ, क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक विकास के लिए सीमाओं के आर-पार लोगों और वस्तुओं की अबाधित आवाजाही सुनिश्चित करना है।

भारत बांगलादेश यात्री बस सेवा की प्रगति समीक्षा

भारत और बांगलादेश के परिवहन, गृह और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने 6 मई को शिलांग में दोनों देशों के बीच यात्री बस सेवा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक की। इससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। बैठक में भारत की ओर से असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय के परिवहन आयुक्त और प्रतिनिधि तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारी शामिल हुए। बांगलादेश के अधिकारियों में सड़क परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और विदेश मंत्रालय तथा बांगलादेश सड़क परिवहन निगम के अधिकारी शामिल थे। दोनों देशों के बस परिचालक भी बैठक में उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच चार मार्गो पर चलने वाली बस सेवाओं का जायजा लेना और यात्रियों के लिए आसान तथा सुविधाजनक यात्रा के लिए संभावित सुधार लाना था।

बैठक में वीजा मंजूरी सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा की गई ताकि तेजी से मंजूरी दी जा सके। इसके लिए बांगलादेश ने अगरतला में उसके मौजूदा वाणिज्य दूतावास को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय ने गुहावाटी में बांगलादेश का एक और वाणिज्य दूतावास स्थापित करने को मंजूरी दी। बैठक में दोनों तरफ यात्री सुविधाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की गई। ■

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राष्ट्रीय राजमार्गों के अवार्ड और निर्माण में 2.5 गुना बढ़ोतरी का लक्ष्य

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वर्ष 2016-17 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गो के अवार्ड और निर्माण के लक्ष्य में 2.5 गुना बढ़ोतरी निर्धारित की है।

अपने मंत्रालय की वर्ष 2015-16 के अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित होकर श्री गडकरी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि पिछले वर्ष जो विकास की गति स्थापित हुई है, उसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान उससे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

उन्होंने 2016-17 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि 2015-16 में 10,000 किलोमीटर अवार्ड दिया गया था। निर्माण लक्ष्य 15,000 किलोमीटर निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 6,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण हुआ था।

अवार्ड के लिए लक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई में से 15,000 किलोमीटर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और 10,000 किलोमीटर मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (एनएचआईडीसीएल) के लक्ष्य के अधीन आएगी। निर्माण के लिए एनएचएआई का लक्ष्य 8,000 किलोमीटर, जबकि मंत्रालय और एनएचआईडीसीएल का लक्ष्य 7,000 किलोमीटर निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2015-16 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए बहुत सकारात्मक परिणामों वाला रहा है। पहली बार 10,000 किलोमीटर से भी अधिक सड़क लम्बाई के कार्य का अवार्ड दिया गया है। 6,000 किलोमीटर का निर्माण पूरा होने से वर्ष दर वर्ष लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। ■

पुस्तक लोकार्पण

'जल है तो कल है संरक्षण ही हल है'

नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में 2 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय सचिव इंजी. अरुण कुमार जैन द्वारा लिखित एवं प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक ''जल ही अमृत है'' का विमोचन किया गया। भाजपा केवल पार्टी और सत्ता के लिए सोच की पार्टी नहीं बल्कि एक वैश्विक सोच की पार्टी है। इसका प्रत्येक कार्यकर्ता विश्व कल्याण की सोच रखता है और सदा उसी के लिए चिंतित रहता है। यह पुस्तक

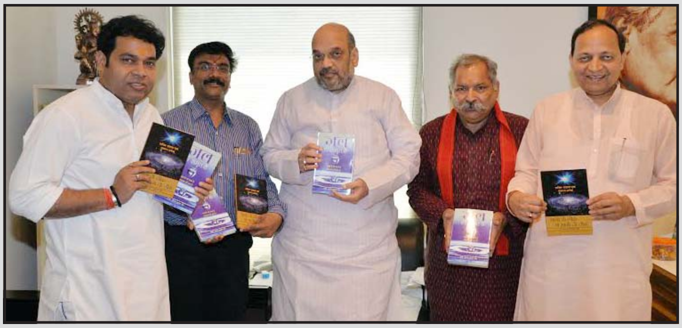

इसी सोच का परिणाम है।

सर्वविदित है कि पूरा विश्व जल के भयावह संकट से ग्रस्त है। लेखक इंजी. अरुण कुमार जैन ने जल की उत्पत्ति से लेकर इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए दैनिक जीवन में इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक उपयोग उपभोग का विषद् वर्णन इस पुस्तक में किया है।

साथ ही उन्होंने इसके संरक्षण की आवश्यकता पर हमारा ध्यानाकर्षण करते हुए संरक्षण के विलक्षण उपायों को भी बड़ी कुशलता से विश्लेषित किया है। यह पुस्तक समीचीन होते हुए पूरे विश्व के लोगों के लिए अति उपयोगी तथा जल संरक्षण के लिए एक प्रेरणास्रोत है। इस पुस्तक की प्रेरणा ''जल है तो कल है, संरक्षण ही हल है'' केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व समुदाय के लिए एक संकल्प वाक्य है। भाजपा समस्त भारतीयों के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व से जल संरक्षण का आह्वान करती है।

इस पुस्तक के विमोचन के समय भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, प्रभात प्रकाशन के निदेशक श्री प्रभात कुमार, भाजपा महासचिव श्री अरूण सिंह जी, भाजपा सचिव श्री श्रीकांत शर्मा व इंजी. अरूण कुमार जैन आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी ने एक साथ जल संरक्षण हेतु क्रियाशील रहने और आवश्यक कदम उठाने का संकल्प लिया। ■

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की ओर...

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल ने महामंत्री प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में 23 जनवरी 2013 से 24 जनवरी 2016 के बीच संपन्न संगठनात्मक कार्यक्रम एवं चुनाव परिणाम से संबोधित विवरण शामिल हैं। इस अवधि में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में जहां पार्टी के 11 करोड़ सदस्य बने और यह संगठनात्मक रूप से अत्यंत सशक्त हुई, वहीं श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। हम यहां महामंत्री प्रतिवेदन का पूरा पाठ क्रमशः प्रकाशित कर रहे हैं। प्रस्तुत है चौथा भागः

संगठनात्मक कार्यक्रम व सेवाकार्य

लगातार चुनाव रहने के कारण अधिकांश कार्यक्रम चुनाव केन्द्रित रहे हैं। फिर भी कुछ विशिष्ट कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं:-

जन कल्याण पर्व: 26 मई 2015 को केन्द्र सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश भर में एक सप्ताह तक सरकार की उपलब्धियों पर प्रेस कांफ्रेंस, प्रदर्शनी, सभायें 35 राज्यों के 206 स्थानों पर आयोजित हुई जिसमें 4,82,170 लोगों की सहभागिता रही। राज्यों के बहुत स्थानों पर बड़े प्रभावी कार्यक्रम हुये। दीनदयाल धाम, मथुरा में प्रधानमंत्री जी की अभूतपूर्व जनसभा हुई जिसमें दो लाख तक संख्या रही।

रक्षाबंधन (बीमा पर्व) : महिला सुरक्षा के लिए देश भर में कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा बंधन के रूप में माताओं, बहनों के जनधन खाते खोले एवं 12 रुपये, 330 रुपए में आम आदमी ने बीमा कराये।

31 अक्टूबर 2015 : सरदार पटेल जयंती पर एकता दौड़, सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण, विचार गोष्ठी, सेमिनार जैसे कार्यक्रम हुये।

सांसदों का सम्पर्क अभियान : सांसद व मंत्रियों द्वारा 30 घंटे तक दो-दो लोकसभा क्षेत्रों में रहकर, जमीनी स्तर पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा हेतु जनता में कार्यक्रम सम्पन्न हुए।

जन स्वाभिमान अभियान : 18, 19, 20 जनवरी 2016 को जेएनयू व हैदराबाद विश्वविद्यालय की घटना पर सभी राज्यों में व जिला केन्द्रों तक कार्यक्रम हुये।

स्वच्छ भारत अभियान : 10 दिनों तक सभी राज्यों में कार्य लिया गया। सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिये राज्यों में विशेष अभियान लिया गया।

मुद्रा योजना : अभी तक 2.7 करोड़ हितग्राहियों को 99,468 करोड़ रुपये का ऋण वितरण करके स्वरोजगार में लगाये गये। पार्टी ने अभियान चलाकर छोटे कामगारों को बैंकों से सहायता करने के लिए प्रयास किये।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस : 21 जून को पूरी दुनिया योगमय हो गयी। मुख्य समारोह दिल्ली में राजपथ पर प्रधानमंत्री जी एवं विभिन्न योग गुरुओं के साथ पचास हजार महिलाओं एवं पुरुषों ने भाग लिया।

गरीब कल्याण योजनायें : प्रभावी क्रियान्वयन में सांसदों की भूमिका- विषय पर 19 अप्रैल 2016 को एक दिन की प्रशिक्षण कार्यशाला की गई, जिसमें सांसदों को क्षेत्र में योजना विस्तार के लिये उपयोगी सूत्र दिये।

संगठनात्मक एवं चुनावी सफलता की दृष्टि से कमजोर राज्यों के लिए विशेष योजनाः असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल के लिए केन्द्रीय प्रभारी मंत्री को संगठन की मजबूती के लिये विशेष कार्य में लगाया गया।

उत्तर पूर्वी राज्य : 16 अप्रैल से 28 अप्रैल तक नार्थ ईस्ट के हर राज्य के जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से प्रत्यक्ष मिलकर संवाद किया और पार्टी की मजबूती के लिए उचित योजनायें

बनायी।

सहयोग : भाजपा मुख्यालय में सरकार से सम्बन्धित कार्यो के लिए प्रतिदिन दोपहर 03.00 बजे से 05.00 बजे तक एक केन्द्रीय मंत्री उपलब्ध रहते हैं।

सुशासन दिवस (25 दिसम्बर) कार्यक्रम : सभी 36 राज्यों के जिला व मंडल केन्द्रों पर केन्द्र सरकार व राज्यों की भाजपा सरकार के उल्लेखनीय कार्यो का प्रचार-प्रसार।

आंदोलनात्मक कार्यक्रम : केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं असम में घोटालों, भ्रष्टाचार व गुंडागर्दी के विरुद्ध आंदोलन, सभायें हुयीं। सैंकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए। गिरफ्तारियां हुई।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक : बेंगलुरू (कर्नाटक) में 3, 4 अप्रैल को कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुयी। जिसमें 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' एवं 'स्वच्छता अभियान' के अंतर्गत सिर पर मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन का संकल्प लेकर देश भर में कार्यकर्ताओं की टीम लग गयी है और 2016 अंत तक इस कुप्रथा से मुक्ति संभव हो सकेगी।

शासन के स्तर पर

मा. श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गांव, गरीब, सेना के जवान, नौजवान, किसानों को समर्पित है। मानवता के आधार पर पड़ोसी एवं अन्य देशों से हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। दलित, शोषित, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह सरकार लगातार कार्यरत है। केन्द्र सरकार द्वारा 20 महीनों में प्रारम्भ की गई जनकल्याणार्थ कुछ प्रमुख योजनायें निम्न हैं :-

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना
- स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- मेक इन इंडिया
- डिजिटल इंडिया
- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ
- स्वच्छ भारत अभियान
- नमामि गंगे अभियान
- JAM - जनधन-आधार-मोबाइल
- उदय-उज्ज्वल डिस्कॉम एश्युरेंस योजना
- किसान फसल बीमा योजना
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- 'कृषि मृदा स्वास्थ्य कार्ड' जारी करना
- मजदूरों के हितों के लिये श्रमेव जयते योजना का शुभारंभ तथा न्यूनतम 1000 पेंशन योजना
- योग दिवस (21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस) पर कार्यक्रम
- सुकन्या समृद्धि खाता योजना
- रेडियो पर प्रधानमंत्री का नियमित संबोधन (मन की बात)
- 100 स्मार्ट सिटी योजना की घोषणा
- 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' योजना

अन्य विशिष्ट उपलब्धियां

- बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती पर विश्व स्तर का संस्थान का शिलान्यास किया।
- घुमन्तू जनजातियों हेतु आयोग का गठन किया गया है।
- ऐतिहासिक नागालैण्ड समझौता (एनएससीएन के साथ)
- नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को भूकंप आपदा पर ऑपरेशन मैत्री, चंद घंटों में राहत व बचाव कार्य किया गया।
- सीमा पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया।
- बांग्लादेश से 40 वर्षो से चल रहा सीमा विवाद खत्म करके ऐतिहासिक समझौता।
- इराक में फंसी भारतीय नर्स, लीबिया व यमन में फंसे 4741 भारतीयों को 48 अन्य देशों में फंसे 1947 नागरिकों को सुरक्षित वापसी करने का सफल ऑपरेशन किया गया।
- 892 पुराने कानूनों को समाप्त करने हेतु प्रभावशाली कदम उठाया।
- गरीबों को एलपीजी कनेक्शन के द्वारा स्वच्छ ईंधन देने का 2000 करोड़ का कार्यक्रम। महिला सशक्तिकरण और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक अनूठा कदम है।
- रेल बजट में दीनदयाल सवारी डिब्बा सहित अंत्योदय एक्सप्रेस की शुरुआत की।
- पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशताब्दी एवं श्री गुरु गोविन्द सिंह जी की 300वीं जन्मशती समारोह आयोजन हेतु 100-100 करोड़ राशि बजट में आवंटित की है।
- हाल ही के बजट में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र पर मुख्य फोकस किया गया है। प्रत्येक योजना में गांव, गरीब, किसान एवं मजदूरों को केन्द्र में रखकर बजटीय आवंटन में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। इन क्षेत्रों में आजादी के बाद से अब तक प्रस्तुत बजट में सर्वाधिक आवंटन किया गया है।
- नीम कोटेड यूरिया के द्वारा खपत में बचत, भूमि सुधार तथा यूरिया की काला बाजारी पर रोक।

- सक्षम किसान- समृद्ध किसान, गांव बढ़ेगा देश बढ़ेगा, हर खेत को पानी (Per Drop-More Crop), दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत मई 2018 तक शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो सकेगा।
- वन रैंक- वन पैंशन की दशकों पुरानी मांग पूर्ण करके धनराशि आवंटित की गयी।
- राष्ट्रीय युद्ध स्मारक निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- कई राज्यों में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हुआ है।

विपदा में सहायता : देश के अंदर हो चाहे बाहर हो, किसी भी प्रकार की आपदा में संगठन व सरकार ने पूरी सक्रियता से पीड़ितों की सहायता की है। असम, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में भीषण बाढ़ के समय पार्टी ने राहत कार्य में सक्रिय भाग लिया।

भाजपा शासित राज्य सरकारों द्वारा भी अनेक जनकल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं। कई राज्यों में परिवर्तन भी स्पष्ट दिख रहा है। गरीबों की आय में वृद्धि, कृषि विकास दर, बालिका जन्म दर में वृद्धि, स्वास्थ्य के क्षेत्र में व जल संसाधन आदि क्षेत्रों में कई राज्यों ने विशेष उपलब्धि प्राप्त की है। पिछले एक वर्ष में संगठन के स्तर पर सबसे बड़े दल के रूप में तथा सरकार के स्तर पर निर्णायक, विश्वसनीय, दिशा देने वाली, भ्रष्टाचार मुक्त तथा दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने वाली सरकार की छवि बनी है।

संगठनात्मक चुनाव

- यह चुनाव का वर्ष था। राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव संपन्न हुए। 24 जनवरी 2016 को श्री अमित शाह सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
- अब तक 21 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं।

हर बूथ पर कार्यक्रम

हर बूथ पर अब वर्ष भर में तीन कार्यक्रम केंद्र की योजना से और तीन कार्यक्रम स्थानीय योजना से होगी। इसकी रूपरेखा की घोषणा कार्यकारिणी में होगी।

समन्वय

- प्रदेश इकाई एवं केंद्र के समन्वय की दृष्टि से केंद्र की बैठक।
- सरकार एवं संगठन के समन्वय की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का महामंत्रियों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक
- समविचारी संगठनों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ समय-समय पर बैठकें हुई, जिससे सहज वातावरण का निर्माण हुआ।
- सांसदों से राज्यवार रात्रि भोजन के साथ बैठक व अनौपचारिक चर्चा हुई। अब तक सभी राज्यों के सांसदों से मुलाकात हो चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों से विदेश नीति को लाभ मिला

पिछले 20 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति की पहल से व्यापक बढ़त दिखाई दे रहा है। उनकी 'एक्ट ईस्ट' नीति से बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, जापान, फिजी तथा आस्ट्रेलिया के अन्य देशों में विस्तृत प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब जापान हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना में बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी बन गया है। मध्य-पूर्व के तेल समृद्ध देशों के साथ अधिक गहन सम्बंध, कनाडा तथा अस्ट्रेलिया के साथ परमाणु ईंधन के लिए आपूर्ति समझौते से हमारी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। भारतीय तथा चीनी नेताओं के साथ नियमित बैठकों से द्विपक्षीय सम्बन्धों में विस्तार हुआ है। अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे पश्चिमी देशो के साथ संबंधों में नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं और अब हमें आतंकवाद संबंधों में भारत के सुरक्षा सम्बन्धों आदि मुद्दों पर अधिक सहयोग मिल रहा है। ये सभी देश भी 'मेक इन इण्डिया', 'डिजिटल इण्डिया', 'स्टार्ट अप इण्डिया' जैसी पहल पर सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं।

प्रधानमंत्री के विदेश दौरों का एक महत्वपूर्ण पहलू विश्व के व्यापारिक नेताओं के साथ मिलकर काम करना भी है। जर्मनी के साथ मिलकर पार्टनर देश के रूप में भागीदारी और सिलीकॉन वैली, यूएसए मे 'डिजीटल इण्डिया' कान्क्लेव में भारत की भागीदारी इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं।

तीसरा महत्वपूर्ण पहलू इण्डियन डायसपोरा के साथ काम करना है। श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, सिंगापुर, मलेशिया, इंग्लैंड, मॉरीशस आदि अनेक देशों में वहां के प्रमुख लोगों को सम्बोधित किया है। इंग्लैंड में हमारे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए ऐतिहासिक बेम्बले स्टेडियम में कड़ी ठण्ड में 60,000 लोगों की असाधारण भीड़ इसका उदाहरण है। इन घटनाओं में न केवल सभी धर्मो और भाषाओं के लोग इकट्ठा हुए, बल्कि स्थानीय राजनीतिज्ञों, नीति-निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं ने भी शामिल होकर इसे अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। कनाडा और इंग्लैंड में इन देशों के प्रधानमंत्रियों ने भी श्री मोदी के साथ डायसपोरा इवेंट्स को सम्बोधित किया जबकि अमरीका, कनाडा तथा इंग्लैंड में स्टेट प्रीमीयर्स, कांग्रेसजन, संसद सदस्य भी यहां उपस्थित रहे।

क्रमशः...